मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्ष: 8 अंक 329
शुक्रवार, 19 जून 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

राहुल गांधी का छात्रों से आह्वानः स्टूडेंट्स इको से जुड़कर शिक्षा-रोजगार पर उठाएं आवाज

कोटा, 18 जून। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को छात्रों और नौकरी चाहने वालों से हाल ही में शुरू किए गए 'छात्रों की गूंज' अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद शिक्षा, परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े उनके मुद्दों को सीधे सरकार तक पहुंचाना है। पर एक पोस्ट में गांधी ने हिंदी में लिखा कि अगर आपने पेपर लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी या बहुत ज्यादा फीस का दर्द सहा है। अगर इस सिस्टम ने आपके सपने तोड़ दिए हैं। अगर आपके परिवार ने आपकी पढ़ाई में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी है। तो सुनिएः स्टूडेंट्स इको आपकी आवाज है।

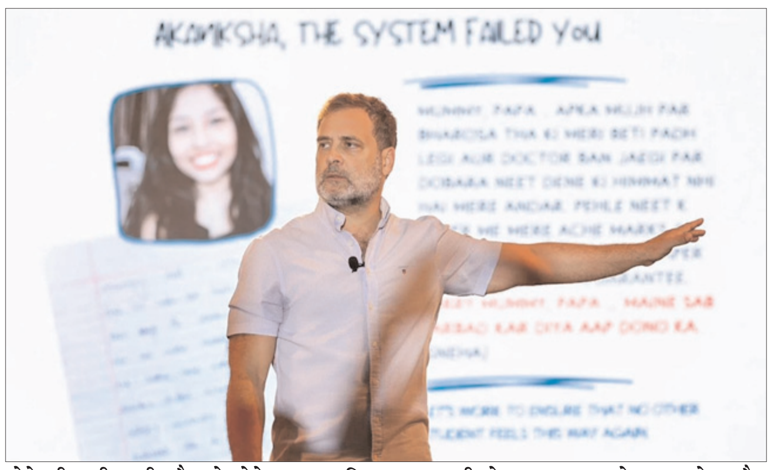

उन्होंने इस मुहिम को सिर्फ.एक मुहिम से कहीं ज्यादा बताया और इसे सरकार के सामने सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाओं और सम्मानजनक रोजगार से जुड़ी माँगें उठाने का एक मंच कहा। गांधी ने सुझाव देकर और इससे जुड़ी याचिका पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल होने की अपील की और जोर देते हुए कहा कि आपका एक हस्ताक्षर इस लड़ाई को मजबूत करेगा। जितने ज्यादा नाम होंगे, आवाज उतनी ही बुलंद होगी। गांधी द्वारा शेयर की गई कैंपेन की जानकारी के अनुसार, प्रतिभागी अपनी जानकारी देकर, सुझाव शेयर करके और पिटीशन पर साइन करके इसमें शामिल हो सकते हैं।

यह अभियान कांग्रेस पार्टी की उस व्यापक कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत छात्रों और नौकरी चाहने वालों से जुड़े मुद्दों–जैसे परीक्षा से जुड़े विवाद, भर्ती में अनियमितताएं और पढ़ाई का खर्च–को उजागर किया जा रहा है। इससे पहले, कांग्रेस ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर ₹छात्रों की गूंज₹ नाम से एक देशव्यापी अभियान की घोषणा की थी। इस पहल में देश भर में और संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन, लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रम और चचाएँ शामिल होंगी। पार्टी ने कहा कि इस अभियान का मकसद कोचिंग फीस, पेपर लीक, शिक्षा तक पहुँच और रोजगार के मौकों जैसे मुद्दों को उजागर करना है।

राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से छात्रों की गूंज महा रैली की अगुवाई करते हुए इस अभियान की शुरूआत की। ठरवक और यूथ कांग्रेस जैसे कांग्रेस संगठनों की भागीदारी के साथ यह अभियान दूसरे इलाकों तक भी फैलाया जाएगा। इस पहल के तहत गांधी इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में होने वाले सम्मेलनों में भी भाषण देंगे।

कर्नाटक में कांग्रेस ने मारी बाजी, एमएलसी चुनाव में जीती 5 सीटें

कर्नाटक, 18 जून। कर्नाटक में डी के शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली चुनावी लड़ाई में, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद की सात सीटों में से पांच पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी भाजपा ने दो सीट जीतीं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) दोनों ही दलों के विधायकों की ओर से 'क्रॉस-वोटिंग' की गई, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों ने विधान सौध में हुए चुनाव में मतदान किया। सात सीटों के चुनाव में आठ उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के थिप्पन्नप्पा कामकनूर, पी. वी. मोहन, बी. के. हरिप्रसाद (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष), शिवन्ना बी एस, और विनय कार्तिक प्रकाश तथा भाजपा के लिंगराज पाटिल और रघु आर और जद (एस) के गोविंदराजू शामिल हैं। कांग्रेस के पांचों उम्मीदवारों और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि जद(एस) के गोविंदराजू को हार का सामना करना पड़ा। यह चुनाव कराने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। इनमें कांग्रेस के नसीर अहमद, टिप्पन्नाप्पा और बी. के. हरिप्रसाद, भाजपा के एन. नागराजू (एमटीबी), प्रताप एस. नायक के. और सुनील वल्लयापुर तथा जद (एस) के गोविंदराजू शामिल हैं।

झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने बदला खेल, एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी जीते

रांची, 18 जून। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार बैजनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी तथा एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा ।

राम को 31 नाथवानी को 28 और झा को प्रथम वरीयता के 19 मत मिले जबकि तीन वोट रद्द कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा के सभी 81 विधायकों ने मतदान किया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई मतगणना के बाद दोनों विजेताओं के नामों की आधिकारिक घोषणा की गई। इस चुनाव में झामुमो के बैजनाथ राम, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी मैदान में थे।

तीन उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में होने के कारण मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था। परिणामों के साथ ही चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। बैजनाथ राम की जीत सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहीं परिमल नाथवानी ने एनडीए के समर्थन के दम पर राज्यसभा की सीट हासिल करने में सफलता प्राप्त की। नाथवानी झारखंड से तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए जबकि राम पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।चुनाव परिणाम के बाद दोनों खेमों में जश्न का माहौल है।

हरियाणा में नशा तस्करों की अब खैर नहीं, 7 जिलों में बनीं 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट

चंडीगढ़, 18 जून। हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए राज्य के सात जिलों में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हैं। यह फास्ट ट्रैक कोर्ट फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक व यमुनानगर में एक-एक होगी, जबकि सिरसा जिले में छह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं। फतेहाबाद जिले में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है।

संबंधित जिलों में अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में बदला गया है और इन न्यायालायों के न्यायाधीश इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश होंगे। जिन जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, वहां नशे की तस्करी से जुड़े केसों की त्वरित सुनवाई संभव हो सकेगी और इस कारोबार में संलिप्त तस्करों को समय से कड़ी सजा मिल पाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है। न्याय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिरसा जिले में सबसे अधिक छह अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीशों की अदालतों को अन्य स्थापित अधिकारी एवं मनोभावी फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन अदालतों में मुख्य रूप से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।

हरियाणा सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब राज्य में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के मामलों में लगातार कार्रवाई हो रही है तथा अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। नई अदालतों के गठन से इन मामलों के त्वरित निपटारे, दोषियों को शीघ्र सजा और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

हरियाणा सरकार का यह कदम केवल न्यायिक व्यवस्था का विस्तार नहीं, बल्कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान को कानूनी मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। यदि इन अदालतों में मामलों का समयबद्ध निपटारा होता है तो नशा तस्करी के खिलाफ राज्य की लड़ाई को बड़ा बल मिल सकता है।

हरियाणा भौगोलिक रूप से पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़ा है, जिसके कारण यह नशा तस्करों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट रूट भी माना जाता है।

राज्य सरकार और पुलिस के लगातार अभियानों के बावजूद नशे का नेटवर्क चुनौती बना हुआ है।

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3,738 एफआइआर दर्ज की गईं और 6,801 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड कार्रवाई मानी गई। वर्ष 2020 से 2025 के बीच राज्य में 20,519 एनडीपीएस के मामले दर्ज हुए और 35,207 गिरफ्तारियां हुईं।

हरियाणा सरकार का दावा है कि प्रदेश के 3,445 गांवों और 774 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है तथा नशे की लत से जूझ रहे लोगों के उपचार के लिए 161 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। नई अदालतें खुलने से राज्य के गांवों और वार्डों को नशामुक्त घोषित करने के अभियान में मदद मिलेगी।

नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत राज्य सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इनमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन प्रमुख रूप से शामिल है। पंचकूला में सात राज्यों के सहयोग से अंतरराज्यीय सचिवालय की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

एमएएनएएस (मानस) हेल्पलाइन के माध्यम से नशा पीड़ितों को उपचार के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

तमिलनाडु में बीजेपी ने अपराध और बिगड़ी कानून-व्यवस्था के खिलाफ किया प्रदर्शन

तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून को चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, बच्चों के खिलाफ अपराधों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की निंदा की गई। इस प्रदर्शन की अगुवाई BJP के राज्य अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने की। इसमें तमिलनाडु BJP के प्रभारी अरविंद मेनन, वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सुंदरराजन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विंग के सचिव वेल्लोर इब्राहिम के साथ-साथ राज्य के उपाध्यक्ष, सचिव, चेन्नई ज़िला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और आम लोग भी शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में प्लेकार्ड लिए थे और ळश्ङ सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपने मुँह पर काले कपड़े बांध रखे थे।

आईपीएल 2027 के शेड्यूल में बदलाव के साथ मैचों की संख्या बढ़ाएगी बीसीसीआई

नई दिल्ली, 18 जून। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देश के अधिकांश हिस्सों में मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचने के लिए आईपीएल को अगले साल से 10 मार्च से 15 मई तक आयोजित करने पर विचार कर रहा है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने यह जानकारी दी।

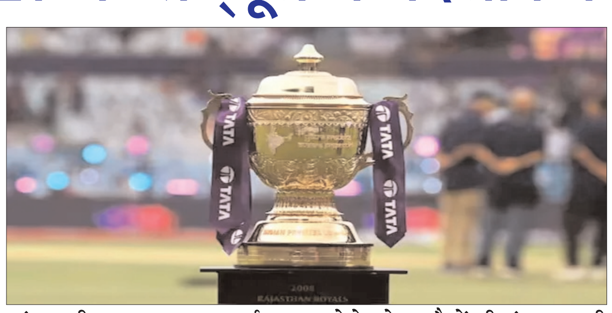

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए मैचों की संख्या 74 ही रहेगी और इसे बढ़ाकर 94 नहीं किया जाएगा। आईपीएल आमतौर पर मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है और मई के अंत तक चलता है। सैकिया ने कहा कि आईपीएल को जल्दी शुरू करने से खिलाड़ी ही नहीं दर्शकों को भी फायदा होगा।

सैकिया ने कहा कि इस साल आईपीएल 28 मार्च को शुरू हुआ और 31 मई तक चला। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कि 15 मई के बाद टूनार्मेंट के अंतिम चरण में बारिश या मानसून से पहले के मौसम से व्यवधान पड़ने की आशंका बनी रहती है। सैकिया ने कहा कि इसके अलावा तब तक मौसम काफी गर्म हो जाता है जो न तो खिलाड़ियों के लिए और ना ही दर्शकों के लिए बहुत अनुकूल है।

बोर्ड के सचिव ने कहा कि मई के अंतिम पखवाड़े में बढ़ते तापमान से निपटने के लिए टूनार्मेंट को दो सप्ताह पहले शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ-साथ हमारी आईपीएल संचालन परिषद में भी इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या हम टूनार्मेंट को मार्च के आखिर के बजाय थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं।

TIWARI'S
SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai - 400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
• Std. XI & XII (Sci.)
• NEET
• JEE (Main & Advance)
• MHT-CET
• Polytechnic & Engg
• Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

आखिरी आदमी की सांसों में बसा कर्मयोद्धा नेता

-ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहते, वे एक युग का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व ऐसा ही एक युगबोध बनकर उभरा है। जून 2026 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि केवल दिनों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उस विश्वास, जनसमर्थन और विकास-यात्रा का प्रतीक है, जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन-प्रणाली और वैश्विक छवि को नई दिशा दी है। लोकतंत्र में किसी नेता की वास्तविक सफलता उसके पद की अवधि से नहीं, बल्कि उसके कार्यों के प्रभाव से मापी जाती है। यदि शासन की कसौटी अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है, तो मोदी युग का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने विकास को सरकारी फाइलों और घोषणाओं से निकालकर सामान्य नागरिक के जीवन तक पहुंचाया है। यह वही अवधारणा है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कहा था-समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने लंबी विकास यात्रा तय की है। जवाहरलाल नेहरू ने नवस्वतंत्र भारत की संस्थागत नींव रखी। लोकतंत्र, वैज्ञानिक चिंतन, सार्वजनिक संस्थानों, शिक्षा, अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला उन्हीं के समय में रखी गई। किंतु समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि योजनाएं बनाना और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। दशकों तक सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी रही, जिसके कारण विकास का बड़ा हिस्सा रास्ते में ही समाप्त हो जाता था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। आर्थिक सुस्ती, भ्रष्टाचार के आरोप, अधूरी परियोजनाएं, प्रशासनिक जड़ता और जनता में घटता विश्वास प्रमुख चिंताएं थीं। ऐसे समय में उन्होंने शासन की परंपरागत शैली को बदलते हुए तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही को केंद्र में रखा। यह परिवर्तन केवल नीतियों का नहीं, बल्कि शासन के दर्शन का परिवर्तन था।

मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली का विस्तार है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल तकनीक को जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था विकसित की गई, जिसने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना संभव बनाया। इससे न केवल भ्रष्टाचार और रिसाव में कमी आई, बल्कि करोड़ों लोगों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि सरकार वास्तव में उनके द्वार तक पहुंच सकती है। गरीब, किसान, महिला, छात्र, वृद्ध और श्रमिक-सभी वर्गों को इसका लाभ मिला। वित्तीय समावेशन की दिशा में जनधन योजना ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जिन परिवारों के पास कभी बैंक खाता नहीं था, वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने। यह केवल बैंक खाते खोलने की योजना नहीं थी, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण का एक नया अध्याय था। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से भरे रसोईघरों से मुक्ति दिलाई। स्वच्छ ईंधन ने उनके स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन किया।

मोदी युग की एक बड़ी पहचान आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार भी है। सड़कों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के क्षेत्र में जिस गति से कार्य हुआ, उसने विकास को नए पंख दिए। आज छोटे शहर भी हवाई संपर्क से जुड़ रहे हैं। गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं। रेलवे का तीव्र आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई हैं। आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए। जिन लोगों ने वर्षों तक कच्ची झोपड़ियों में जीवन बिताया, उनके लिए अपना घर केवल एक भवन नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया। शौचालय निर्माण अभियान ने स्वच्छता को जनांदोलन का रूप दिया। ये परिवर्तन केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जीवन स्तर में दिखाई देते हैं।

कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने किसानों के लिए आय के नए अवसर खोले हैं। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ऊजार्दाता के रूप में भी उभर रहे हैं। जैव ईंधन, प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के प्रयास किए गए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। आज भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बन गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आर्थिक लेन-देन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल तकनीक का उपयोग केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सुशासन का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार और प्रशासन-हर क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत केवल एक विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की क्षमता वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। जी-20 की सफल अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली उपस्थिति, वैश्विक संकटों में संतुलित भूमिका और विकासशील देशों की आवाज बनने का प्रयास भारत की बढ़ती शक्ति को दशार्ता है। इनदिनों के जी-7 शिखर सम्मेलन में सदस्य न होने पर भी मोदी का दबदबा होना- विदेश नीति में आत्मविश्वास और संतुलन के नये स्वर द्दशाता है। मोदी युग की एक विशेषता यह भी है कि उसने राष्ट्रवाद को विकास से जोड़ा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का अभियान है। रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां इसी सोच का परिणाम हैं। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निमार्ता और नवप्रवर्तक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास-ये केवल राजनीतिक नारे नहीं, बल्कि शासन के मार्गदर्शक सूत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। इनका उद्देश्य विकास को समावेशी बनाना है, ताकि समाज का कोई वर्ग पीछे न रह जाए। यही कारण है कि विकास योजनाओं का केंद्र अब वही व्यक्ति है, जो कभी व्यवस्था के हाशिए पर खड़ा था। निस्संदेह, किसी भी लंबे शासनकाल की तरह मोदी सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस और आलोचना भी होती रही है। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक और आवश्यक है। किंतु यह भी सत्य है कि पिछले बारह वर्षों में शासन की कार्यशैली, विकास की गति और नागरिकों की अपेक्षाओं में एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। आज नागरिक केवल वादे नहीं सुनना चाहता, बल्कि परिणाम देखना चाहता है। यही लोकतांत्रिक परिपक्वता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि उन्होंने शासन को एक जनांदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया है। वे स्वयं को शासक नहीं, बल्कि ह्यप्रधान सेवकह्ण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कार्यशैली में निरंतरता, परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का भाव दिखाई देता है। यही कारण है कि वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और विश्व मंच पर भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए हैं।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं है। यह एक ऐसे भारत की परिकल्पना है जो आत्मनिर्भर, समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत, सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से संवेदनशील हो। इस दिशा में मोदी युग ने अनेक आधारभूत परिवर्तन किए हैं, जिनका प्रभाव आने वाले दशकों में और अधिक स्पष्ट होगा। आज जब भारत अमृतकाल की यात्रा पर अग्रसर है, तब यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का योगदान केवल योजनाओं और परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों में यह विश्वास जगाया है कि परिवर्तन संभव है, विकास सबका अधिकार है और राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अंत्योदय से विकसित भारत तक की यह यात्रा उसी विश्वास, संकल्प और कर्मयोग की कहानी है, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण को नई गति और नई दिशा प्रदान की है।

हरित पुनरुद्धार की ओर बढ़ते भारत के कदम

- महेन्द्र तिवारी

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने भूमि बहाली के क्षेत्र में एक ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है जिसने पूरी दुनिया के सामने सफलता का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। भारत ने अपने निरंतर और सुनियोजित प्रयासों से 21.76 मिलियन हेक्टेयर बंजर और खराब हो चुकी भूमि को फिर से हरा-भरा और उपजाऊ बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस विशाल आंकड़े की गंभीरता और इसके भौगोलिक विस्तार को इस तरह समझा जा सकता है कि यह क्षेत्रफल लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के कुल भौगोलिक आकार के बराबर है। इतने बड़े पैमाने पर सूखी, ऊसर और जीवनहीन हो चुकी जमीन को पुनर्जीवित करना केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं है बल्कि यह प्रकृति के प्रति देश की गहरी प्रतिबद्धता और दूरगामी नीतियों का जीवंत परिणाम है। इस ऐतिहासिक कदम ने न केवल भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा को मजबूत किया है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश की साख को बहुत ऊंचा किया है। भूमि का इस तरह से पुनरुद्धार करना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखने जैसा है जो सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।

इस पूरी मुहिम की वैश्विक कड़ियों को जोड़कर देखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि भारत के ये प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे बड़े अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इसी संदर्भ में बॉन चुनौती का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। बॉन चुनौती वास्तव में वनों की कटाई को रोकने और मरुस्थलीकरण के कारण बंजर हो चुकी भूमि को फिर से उपजाऊ और हरा-भरा बनाने का एक बहुत बड़ा वैश्विक संकल्प है। इस महत्वपूर्ण पहल की शुरूआत वर्ष 2011 में जर्मनी की सरकार और इंटरनेशनल यूनियन फॉर Conservation ऑफ नेचर द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। जब इसे वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया था तब इसका प्राथमिक लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2020 तक पूरी दुनिया में 150 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को बहाल किया जाएगा। इसके बाद इस लक्ष्य को और अधिक विस्तारित करते हुए वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया गया। भारत ने इस वैश्विक चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को इसके साथ इस तरह जोड़ा कि आज देश इस दिशा में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है।

भारत की इस पर्यावरणीय यात्रा में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब देश ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक विस्तार देने का निर्णय लिया। वर्ष 2019 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के चौदहवें सत्र का आयोजन किया गया था जिसे कॉप 14 के नाम से भी जाना जाता है। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के पर्यावरणविदों और नीति निमार्ताओं की उपस्थिति में भारत ने अपने पुराने लक्ष्यों में बड़ा संशोधन किया। भारत ने वैश्विक मंच पर यह संकल्प लिया कि वह वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर और निम्नीकृत भूमि को पूरी तरह से बहाल करेगा। वर्तमान समय में हासिल किया गया 21.76 मिलियन हेक्टेयर का यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और वह इस अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले ही प्राप्त करने की मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है।

इस विशाल भूभाग को दोबारा जीवन देने और उसे हरा-भरा बनाने के लिए देश में बहुआयामी रणनीतियों को अपनाया गया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वनरोपण की रही है। देश के विभिन्न राज्यों में जो जमीनें पूरी तरह से खाली थीं या जहां औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों के बाद खदानों को बंजर छोड़ दिया गया था वहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए गए। इस प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि केवल पेड़ न लगाए जाएं बल्कि उन स्थानीय प्रजातियों के पौधों को चुना जाए जो वहां की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हों। इससे बंजर पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में एक बार फिर से सघन हरित आवरण लौटने लगा जिसने भूमि के क्षरण को रोक दिया और मिट्टी की खोई हुई पोषक क्षमता को वापस लाने में मदद की।

वनरोपण के साथ-साथ जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए जलागम प्रबंधन तकनीक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया जो इस सफलता की रीढ़ साबित हुई। इसके अंतर्गत पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धतियों से छोटे-छोटे बांधों का निर्माण किया गया जिन्हें चेक डैम कहा जाता है। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा के तेजी से बहते हुए पानी को रोका गया जिससे न केवल उपजाऊ मिट्टी का बहाव थमा बल्कि जमीन के भीतर पानी का स्तर भी तेजी से ऊपर उठा। भूजल स्तर में सुधार होने के कारण आसपास की सूखी और प्यासी जमीन को पर्याप्त नमी मिली जिससे वहां प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों का उगना दोबारा शुरू हो गया और कई सूखी नदियां तथा जलस्त्रोत पुनर्जीवित हो उठे।

इस अभियान की एक और बड़ी विशेषता कृषि वानिकी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना रही है जिसने पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों को सकारात्मक रूप से बदल दिया। परंपरागत रूप से किसान केवल अपनी फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते थे लेकिन नई नीतियों के तहत उन्हें खेतों की मेड़ों पर और फसलों के बीच के खाली स्थानों में आर्थिक रूप से उपयोगी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया। इससे किसानों को न केवल ईंधन और चारे के रूप में अतिरिक्त संसाधन मिले बल्कि खेतों की मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता और सामान्य उर्वरता में भी भारी सुधार हुआ। कृषि वानिकी ने देश के ग्रामीण अंचलों में एक नए प्रकार के लाभदायक और टिकाऊ हरित तंत्र को जन्म दिया जिसने पर्यावरण के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को भी संबल प्रदान किया।

इन सभी सरकारी और तकनीकी प्रयासों को वास्तविक शक्ति और गति तब मिली जब इसमें आम जनता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया। संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत वनों के आसपास रहने वाले स्थानीय ग्रामीण निवासियों और विशेषकर आदिवासी समुदायों को जंगलों की रक्षा करने और नए पौधे लगाने की सीधी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब इन समुदायों को यह अहसास हुआ कि जंगलों का विकास सीधे तौर पर उनके अपने जीवन, संस्कृति और आजीविका से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। लोगों के इस सामूहिक जुड़ाव के कारण ही नए लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई और सामुदायिक वनों का दायरा तेजी से बढ़ने लगा।

इस ऐतिहासिक भूमि बहाली अभियान के दूरगामी और बहुआयामी लाभ अब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे हैं जिनमें सबसे बड़ा लाभ एक विशाल कार्बन अवशोषक क्षेत्र का निर्माण होना है। जब 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर नए पेड़-पौधे और घनी वनस्पतियां विकसित होती हैं तो वे वायुमंडल से हर साल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोख लेती हैं। यह प्रक्रिया वैश्विक तापन के खतरों को कम करने में भारत की ओर से विश्व को दिया गया एक अमूल्य योगदान है। यह हरित क्षेत्र देश के कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने में एक मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है और वैश्विक जलवायु सुधार में अपनी महती भूमिका निभा रहा है।

इसके साथ ही जैव विविधता की बहाली इस अभियान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि जो क्षेत्र कभी पूरी तरह से उजाड़ और बेजान हो चुके थे वहां अब एक बार फिर से विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को अपना खोया हुआ प्राकृतिक आवास मिल रहा है। पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों और मिट्टी के भीतर रहने वाले सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होने से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र दोबारा सक्रिय हो रहा है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अंततः इस पूरी प्रक्रिया ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई और अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की है जो सतत विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। भूमि के उपजाऊ होने से जहां एक ओर कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है वहीं दूसरी ओर जंगलों से मिलने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे फल, शहद, गोंद और अनेक प्रकार की दुर्लभ जड़ी-बूटियों ने स्थानीय लोगों की दैनिक आय को बढ़ाने में मदद की है। रोजगार के नए अवसर पैदा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आई है जो यह सिद्ध करती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है।

वर्दी के उस पार : पुलिस नहीं, समाज का चेहरा

- राजकुमार जैन, स्वतंत्र लेखक

लोकतंत्र में पुलिस शायद उन विरल संस्थाओं में से एक है, जो एक साथ विश्वास, भय, अपेक्षा और असंतोष का केंद्र बनी रहती हैं। दुनिया के लगभग हर समाज में पुलिस व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठते हैं—कहीं भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं अधिकारों के अतिक्रमण को लेकर, तो कहीं नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के अभाव को लेकर। इन प्रश्नों का उठना लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का संकेत है, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक संस्था को आलोचना से परे नहीं माना जा सकता।

किन्तु इस बहस के बीच एक ऐसा प्रश्न है, जिसे हम प्रायः अनदेखा कर देते हैं। क्या पुलिस वास्तव में केवल एक प्रशासनिक संस्था है, अथवा वह उस समाज का प्रतिरूप भी है, जिसने उसे जन्म दिया है? हमारी सामान्य प्रवृत्ति पुलिस और समाज को दो पृथक संसारों की तरह देखने की है। मानो वर्दी पहनते ही कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों और संस्कारों से मुक्त होकर किसी अलग ही व्यवस्था का हिस्सा बन जाता हो। जबकि सच इसके ठीक विपरीत है। पुलिसकर्मी किसी अन्य ग्रह से नहीं आते। वे उसी मिट्टी में जन्म लेते हैं, उसी पारिवारिक वातावरण में बड़े होते हैं, उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन्हीं सामाजिक मान्यताओं को आत्मसात करते हैं और उन्हीं आकर्षणों, दबावों तथा महत्वाकांक्षाओं के बीच अपना व्यक्तित्व गढ़ते हैं, जिनके बीच हम सब अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

इस दृष्टि से देखें तो पुलिस समाज से बाहर खड़ी संस्था नहीं, बल्कि समाज की संगठित अभिव्यक्ति है। इसलिए जब हम पुलिस की किसी विकृति पर उंगली उठाते हैं, तब कहीं न कहीं उस सामाजिक संरचना की ओर भी संकेत कर रहे होते हैं, जिसने उन विकृतियों को जन्म दिया है।

वास्तविक संकट पुलिस से अधिक हमारे सामूहिक नैतिक चरित्र का है। हम कानून के शासन की बात करते हैं, किंतु जब वही कानून हमारे हितों के प्रतिकूल पड़ता है, तो उसके अपवाद खोजने लगते हैं। हम निष्पक्षता का समर्थन करते हैं, परंतु अपने परिचितों के लिए विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। हम भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से कोसते हैं, किंतु निजी सुविधा के लिए उसी भ्रष्टाचार का सहारा लेने में संकोच नहीं करते।

विडंबना यह है कि हम नियमों के पालन की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, स्वयं से नहीं।

यदि कोई अधिकारी प्रभाव, धन अथवा सामाजिक दबाव के आगे झुक जाए, तो उसे व्यवहारकुशल कहा जाता है; लेकिन यदि वही अधिकारी नियमों का कठोरता से पालन करे, तो उसके लिए संवेदनहीन, अक्खड़ या भ्रष्ट जैसे विशेषण खोज लिए जाते हैं। यह विरोधाभास केवल पुलिस व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का दर्पण है, जिसमें नैतिकता को सिद्धांत नहीं, सुविधा की वस्तु समझ लिया गया है।

किसी भी राष्ट्र की संस्थाएँ शून्य में निर्मित नहीं होतीं। वे उसी सांस्कृतिक और नैतिक वातावरण की उपज होती हैं, जिसमें समाज साँस लेता है। यदि किसी समाज में प्रभाव को योग्यता से अधिक महत्व मिलता हो, यदि सफलता को चरित्र से ऊपर रखा जाता हो और यदि सत्य की तुलना में सुविधा अधिक आकर्षक लगती हो, तो उसकी संस्थाओं में भी वही प्रवृत्तियाँ दिखाई देंगी।

निस्संदेह, इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस की कमियों को अनदेखा कर दिया जाए। शक्ति का दुरुपयोग, अन्याय और भ्रष्टाचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकते। लोकतंत्र में जवाबदेही अनिवार्य है। परंतु केवल संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता। यदि हम परिणामों पर आक्रोश व्यक्त करते रहें और उनके सामाजिक कारणों को समझने से बचते रहें, तो सुधार की प्रक्रिया अधूरी ही रहेगी।

हमारे सार्वजनिक विमर्श की एक और दुर्बलता है। हम अच्छाई को सामान्य मान लेते हैं और बुराई को असाधारण घटना बनाकर प्रस्तुत करते हैं। दंगों, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय हजारों पुलिसकर्मी अपने परिवारों से दूर रहकर समाज की सुरक्षा में लगे रहते हैं। अनेक बार वे अपने स्वास्थ्य और जीवन तक को जोखिम में डाल देते हैं। किंतु उनके त्याग की कहानियाँ प्रायः चर्चा का विषय नहीं बनतीं।

इसके विपरीत, किसी एक अधिकारी की गलती पूरे पुलिस तंत्र की पहचान बना दी जाती है।

एक परिपक्व समाज का दायित्व केवल अन्याय की आलोचना करना नहीं, बल्कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान करना भी है। सत्य न तो केवल निंदा में निहित है और न केवल प्रशंसा में; वह दोनों के बीच संतुलित दृष्टि में निवास करता है।

दरअसल, पुलिस पर होने वाली हर चर्चा समाज के आत्ममंथन का अवसर भी होनी चाहिए। यदि दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा असुंदर लगे, तो दोष दर्पण का नहीं होता। दर्पण तो केवल वही दिखाता है जो उसके सामने उपस्थित है। पुलिस भी कुछ ऐसी ही संस्था है। उसमें हमें अपने ही समाज का अनुशासन, अपनी ही नैतिकता, अपने ही समझौते और अपनी ही कमजोरियाँ प्रतिबिंबित दिखाई देती हैं।

इसलिए स्थायी परिवर्तन केवल नए कानूनों, आयोगों या प्रशासनिक सुधारों से नहीं आएगा। उसका आरंभ मनुष्य के भीतर होगा। जब परिवार सफलता के साथ सत्यनिष्ठा का संस्कार देंगे, जब विद्यालय उपलब्धियों के साथ चरित्र निर्माण को भी महत्व देंगे, और जब नागरिक स्वयं नियमों के पालन को अपना नैतिक दायित्व मानेंगे, तभी संस्थाएँ भी बदलेंगी।

किसी व्यवस्था का वास्तविक उत्थान संसदों, सचिवालयों और पुलिस मुख्यालयों से पहले नागरिक के अंतःकरण में प्रारंभ होता है।

अंततः पुलिस सुधार का प्रश्न समाज सुधार से अलग नहीं है। पुलिस कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि उसी समाज का अनुशासित और संगठित रूप है, जिसे हमने अपने व्यवहार, मूल्यों और प्राथमिकताओं से निर्मित किया है।

इसलिए पुलिस को बदलने की आकांक्षा से पहले हमें स्वयं से यह पूछना चाहिए—क्या हम ऐसे समाज के निर्माण के लिए तैयार हैं, जिसकी वर्दी को देखकर हमें आलोचना नहीं, गर्व का अनुभव हो?

गहलोत और पायलट की मुस्कान के पार कांग्रेस का सियासी सच

- निरंजन परिहार

राजस्थान में कांग्रेसी राजनीति की उड़ान उलझन भरी है। बरसों सत्ता में रहने वाली ताकतवर कांग्रेस राजनीतिक धरातल पर कमजोर लगती है, तो कभी कभार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने की हुंकार भरती हुई भी दिखती है। इसीलिए अपने नेताओं में ताल मेल और मोलजोल भरी मुलाकातों की तस्वीरें उत्साह जगाती हैं, और होठों पर हंसी और चेहरों पर मुस्कान भरी हाथ मिलाते हुए तस्वीरें देखते ही कांग्रेसी चिहुंच उठते हैं। लेकिन राजस्थान की कांग्रेसी राजनीति के सारे सच समझने के लिए तस्वीरों के पार का सच समझने की जरूरत है। राजनीति में तस्वीरें अक्सर वही दिखाई जाती हैं, जिसे दिखाना जरूरी होता है। लेकिन राजनीति की असली कहानी उन तस्वीरों के पार होती है, जहां कैमरे की रोशनी नहीं पहुंचती। राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुस्कुराती तस्वीरें चर्चा में हैं। राहुल गांधी की कोटा यात्रा के दौरान दोनों नेताओं का आत्मीयता से हाथ मिलाना और चेहरे पर सहज मुस्कान लिए हंसते हुए दिखाई देना कांग्रेस कार्यकताओं के लिए राहत और उत्साह का कारण बना। लेकिन राजनीति की तस्वीरों में दिखने वाली निकटता और राजनीतिक वास्तविकताओं की दूरी के बीच अक्सर लंबा फासला होता है, और उसी सच को समझने की जरूरत है।

पिछले एक दशक से राजस्थान कांग्रेस दो समानांतर राजनीतिक धाराओं के बीच बह रही है। एक धारा अनुभव, संगठनात्मक कौशल और सत्ता संचालन की कला का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका चेहरा अशोक गहलोत हैं। दूसरी धारा महत्वाकांक्षा, नई पीढ़ी की राजनीति और भविष्य के नेतृत्व की आकांक्षा का प्रतीक है, जिसका नेतृत्व सचिन पायलट करते हैं। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दोनों की अपनी ताकत है, दोनों का अपना जनाधार है और दोनों की राजनीतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव सत्ता के शिखर तक पहुंचना ही है। राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई दोष नहीं होती। बल्कि यही वह ईंधन है, जिससे राजनीतिक यात्राएं आगे बढ़ती हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कोई नेता अपनी महत्वाकांक्षा को कितनी कुशलता से राजनीतिक रणनीति में बदल पाता है। अशोक गहलोत ने अपने 50 साल के लंबे अनुभव से राजनीति की यह ललित कला सिद्ध कर रखी है। और सचिन पायलट अभी अपने राजनीतिक भविष्य को उस मुकाम तक पहुंचाने के संघर्ष में हैं, जहां नेतृत्व केवल संभावना नहीं, बल्कि निर्विवाद स्वीकार्यता बन जाए।

राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी यही है और विडंबना भी। विडंबना इसलिए कि पार्टी का बड़ा हिस्सा दो खेमों में बंटा दिखाई देता है। ताकत इसलिए कि दोनों नेताओं की सक्रियता ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से जीवंत, जीवित और प्रासंगिक बनाए रखा है। बीजेपी के मजबूत संगठन और सत्ता की निरंतरता के बीच कांग्रेस यदि आज भी मुकाबले की स्थिति में दिखाई देती है, तो उसके पीछे इन दोनों नेताओं की निरंतर राजनीतिक सक्रियता की बड़ी भूमिका है। समस्या वहीं पैदा होती है, जहां व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षाएं सामूहिक संगठनात्मक लक्ष्यों से बड़ी दिखने लगती हैं। कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता की पीड़ा भी यही है। वह चाहता है कि गहलोत और पायलट साथ दिखें ही नहीं, साथ चलें भी। क्योंकि उसे मालूम है कि राजस्थान में कांग्रेस का पुनरुत्थान किसी एक नेता की ताकत से संभव नहीं है। इसके लिए दोनों धाराओं का संगम आवश्यक है।

यही कारण है कि जब-जब गहलोत और पायलट की मुलाकात होती है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद का वातावरण बनता है। लेकिन उम्मीद और विश्वास में अंतर होता है। उम्मीद तस्वीरों से पैदा हो जाती है, विश्वास व्यवहार से बनता है। और राजस्थान कांग्रेस अभी उस विश्वास की तलाश में है, जो केवल मंच साझा करने से नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं को साझा करने से पैदा होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अपने अपने गुट भी बनाने की फिराक में हैं। लेकिन यह भी एक राजनीतिक यथार्थ है कि राजस्थान कांग्रेस की असली धुरी अभी भी गहलोत और पायलट ही हैं। संगठन की कमान किसी के हाथ हो सकती है, लेकिन जनभावनाओं और राजनीतिक विमर्श का केंद्र वही नेता बनते हैं, जिनकी स्वीकार्यता प्रदेशव्यापी होती है। डोटासरा और जूली चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मगर स्वीकार्यता की प्रदेशव्यापी कसौटी पर आज भी कांग्रेस में अशोक गहलोत नंबर वन और पायलट नंबर दो हैं, और डोटासरा - जूली इन दोनों नेताओं का विकल्प नहीं बन सकते।

असल में, राजनीति केवल पद का खेल नहीं है। पद किसी को अधिकार दे सकते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं। प्रभाव संघर्ष, स्वीकार्यता और जन विश्वास से पैदा होता है। डोटासरा और जूली पद के नेता हैं, कद के नहीं। मगर, गहलोत और पायलट दोनों ने अलग-अलग रास्तों से यह प्रभाव अर्जित किया है। इसलिए दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दो राजनीतिक शैलियों, दो पीढ़ियों और दो दृष्टिकोणों की प्रतिस्पर्धा भी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी राजनीतिक सफलताएं प्रतिस्पर्धा से नहीं, समन्वय से जन्म लेती हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पार्टी है, जिससे कभी भी जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की असली चुनौती अपने भीतर वह विश्वास पैदा करना है, जो कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला सके कि पार्टी का भविष्य व्यक्तिगत समीकरणों का बंधक नहीं बनेगा।

राजस्थान की जनता भी अब केवल राजनीतिक संदेशों से संतुष्ट नहीं होती। वह राजनीतिक व्यवहार को देखती है, नेताओं के संबंधों को परखती है और उनके निर्णयों से निष्कर्ष निकालती है। इसलिए तस्वीरों में मुस्कान जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह राजनीतिक संदेश है, जो उन मुस्कानों के पीछे छिपा होता है। कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त बेहद निर्णायक हैं। विधानसभा चुनाव में केवल दो साल बचे हैं। यदि गहलोत का अनुभव और पायलट की ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो पार्टी नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकती है। लेकिन यदि तस्वीरों की मुस्कानें केवल अवसरों की औपचारिकता बनी रहीं, तो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें फिर निराशा में बदल सकती हैं। आखिरकार राजनीति में हाथ मिलाने से ज्यादा जरूरी दिलों का मिलना होता है। क्योंकि जब दिल मिलते हैं, तब संगठन मजबूत होते हैं। और जब संगठन मजबूत होते हैं, तभी जनता का विश्वास लौटता है। राजस्थान कांग्रेस की असली परीक्षा भी यही है कि वह तस्वीरों की दोस्ती को राजनीतिक एकजुटता में कितना बदल पाती है। बाकी तो खैर, तस्वीरें तो बेचारी कल भी खिंचती थीं, आज भी खिंच रही हैं और आगे भी खिंचती रहेंगी। मगर कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेसियों के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए।

भिवंडी में वर्षों बाद खुला परशुराम पाड़ा-राऊत पाड़ा शिवपाणंद मार्ग, ग्रामीणों ने तहसीलदार का जताया आभार

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। वर्षों से अतिक्रमण और विवाद के कारण बंद पड़ा परशुराम पाड़ा से राऊत पाड़ा को जोड़ने वाला पारंपरिक शिवपाणंद मार्ग आखिरकार प्रशासन के आदेश के बाद खोल दिया गया है। तहसीलदार के निर्णय और राजस्व विभाग की कार्रवाई से किसानों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार राऊत पाड़ा के किसानों के लिए खेतों तक पहुंचने का यह महत्वपूर्ण मार्ग लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में था। कई बार अनुरोध करने के बावजूद संबंधित जमीन मालिकों द्वारा रास्ता खाली नहीं किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से भिवंडी तहसीलदार कार्यालय में दावा दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार ने ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के बाद राजस्व प्रशासन ने पुलिस बंदोबस्त में अतिक्रमण हटाकर शिवपाणंद मार्ग को पूरी तरह खुला कर दिया। मार्ग खुलने से अब किसान, खेत मजदूर, पशुधन, बैलगाड़ी तथा ट्रैक्टर सीधे खेतों तक पहुंच सकेंगे। रास्ता खुलने से ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रशासन का आभार माना। इस अवसर पर मंडल अधिकारी भुरकुट, तलाठी अविनाश चव्हाण, सुभाष पाटिल, पंकज ताल्या, अनंत भोईर, दाभाड पुलिस पाटिल दीपक धुले, किरवली पुलिस पाटिल कुणाल पाटिल, सरपंच अश्विनी वाघे, नंदा वाघे तथा शिवपाणंद आंदोलन के ठाणे जिला समन्वयक शिवाजी राऊत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बताया कि इस संघर्ष में शिवपाणंद सड़क आंदोलन के महाराष्ट्र अध्यक्ष शरद पवले का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। साथ ही भिवंडी तहसीलदार के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया गया। ग्रामीणों का मानना है कि इस फैसले से तालुका के अन्य बंद पड़े शिवपाणंद मार्गों को भी खुलवाने की उम्मीद जगी है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि किसानों और ग्रामीणों की एकजुटता से न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

चाकू की नोक पर डकैती का फर्जी नाटक रचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, 2.94 लाख रुपये बरामद

मीरा रोड (उत्तरशक्ति)। मीरा रोड, नयानगर पुलिस ने चाकू की नोक पर डकैती की एक कथित वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी और उसके सहयोगियों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से डकैती में दिखाई गई पूरी 2 लाख 94 हजार रुपये की नकद राशि बरामद कर कंपनी को वापस सौंप दी है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता उजमा रियाज खान (26 वर्ष), निवासी सिद्धार्थ नगर, नयानगर पूर्व, मीरा रोड, फाइव टेक इंटरनेशनल कंपनी के कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 मार्च 2026 को शाम करीब 5:30 बजे दो अज्ञात व्यक्ति कार्यालय में घुस आए, शटर बंद कर उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया और मेज की दराज में रखे 2.94 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर नयानगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 309(4), 329(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुजम्मिल अब्दुल हाफिज ज सिद्दीकी (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने अपने साथी मोहम्मद ओवेश मोइद्दीन शेख तथा शिकायतकर्ता के साथ मिलकर डकैती का फर्जी नाटक रचा था। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में दर्शाई गई पूरी 2,94,000 रुपये की नकद राशि बरामद कर ली। बाद में यह राशि चेक के माध्यम से फाइव टेक इंटरनेशनल कंपनी के प्रबंधक सोहेल अनवर कुरेशी को सौंप दी गई। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण, सहायक पुलिस आयुक्त सोहेल शेख तथा नयानगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमर जगदाले के मार्गदर्शन में अपराध जांच दल ने सफलतापूर्वक अंजाम दी।

उत्तर प्रदेश में एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, एमबीवीवी क्राइम ब्रांच सेल-4 की बड़ी कार्रवाई

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा सेल-4 ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संचालित एमडी ड्रग निर्माण कारखाने का पदार्फाश किया है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये मूल्य के मादक पदार्थ, रसायन और प्रयोगशाला उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, 4 अप्रैल 2026 को नयानगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बैंक रोड स्थित छेड़ा आदर्श बिल्डिंग में रहने वाली फिरदौस अरबाज कुरैशी के घर पर छापेमारी के दौरान 1 किलो 324 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 2 करोड़ 66 लाख 17 हजार 280 रुपये आंकी गई। जांच में यह मादक पदार्थ उनके पति अरबाज वकील कुरैशी का होने का खुलासा हुआ। इसके बाद दोनों के खिलाफ नयानगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 102/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराध की गहन जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान मुंबई के अग्रिपाड़ा, मालवानी, मनोरी तथा तेलंगाना के जाहिराबाद क्षेत्र में छापेमारी कर 20.72 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ, रसायनिक सामग्री और ड्रग निर्माण में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए। मामले में फरार आरोपी तस्लीम आरिफ चुट्टन उर्फ रज्जाक को 16 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और जांच के आधार पर पुलिस ने वहां संचालित एक एमडी ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 1 किलो 26 ग्राम एमडी ड्रग, 300 लीटर मोनो मिथाइलमाइन (एमएमए) रसायन तथा ड्रग निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न प्रयोगशाला उपकरण बरामद किए गए। जब्त किए गए उपकरणों में हीटिंग ड्रायर, सेपरेशन फ्लास्क, हीटिंग मेंटल रिकवरी फ्लास्क, फोर फिंगर क्लैंप, एडिशन पॉट और बुचरन फनल शामिल हैं।

जब योग विद यूथ 2026 ने इंटरनेशनल योग दिवस 2026 से पहले एक हजार से ज्यादा युवा दिमागों को एक साथ लाया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। भारत की हमेशा रहने वाली योगिक विरासत और युवाओं की ताकत के एक शानदार जश्न में, मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया ने इतिहास बनते देखा, जब 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, युवा प्रोफेशनल्स और वेलनेस के शौकीन लोग योग विद यूथ 2026 के लिए एक साथ आए, जो इंटरनेशनल योग दिवस 2026 का तीसरा ऑफिशियल काउंटडाउन इवेंट है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के साथ मिलकर यह इवेंट आयोजित किया, जिसने देश की सबसे कीमती जगहों में से एक को वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी और कलेक्टिव कॉन्शसनेस का एक वाइब्रेंट सेंटर बना दिया। स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग इ स्वस्थ आयु के लिए योगइ थीम के तहत हुए इस इवेंट में युवा भारत की भावना दिखाई दी, जो वेलनेस, हार्टफुलनेस मेडिटेशन और मकसद भरी जिंदगी को अपनाते हुए एक स्वस्थ और मजबूत देश के विजन को आगे बढ़ा रहा है। इस ऐतिहासिक सभा में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखे हुए विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने में योग की बदलाव लाने वाली भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की दूर की सोच वाली लीडरशिप में, योग एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है जिसने सेहत, तालमेल और अंदरूनी भलाई के यूनिवर्सल मूल्यों के जरिए इंसानियत को एक किया है।

'योगा विद यूथ 2026' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स पर बात करते हुए, हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड परम पूज्य दाजी (कमलेश डी. पटेल) ने कहा:आज लोगों की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी यह दिखाती है कि योग को अपनाने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। योग मन, शरीर और आत्मा का मिलन है। जब इसे ध्यान के साथ जोड़ा जाता है, तो यह आंतरिक अखंडता को एक नए स्तर पर ले जाता है।

यह आपको ईश्वर के करीब लाता है। भारत योग का जन्मस्थान है और आज हम दुनिया में संपूर्ण स्वास्थ्य (होलिस्टिक वेलनेस) के लिए एक मिसाल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया। तब से यह लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है।

हार्टफुलनेस में हम योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।

योग दिलों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाता है : सीमा सिंह

मुंबई (उत्तरशक्ति)। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है,बल्कि यह भावनाओं को संतुलित करके लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। योग अभ्यास से तनाव दूर होता है,सहानुभूति जागृत होती है और एक-दूसरे के साथ जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांद्रा के ताजलैंड सन होटल में मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रेय द्वारा आयोजित योग दिवस पर बोलते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर अनेक जानी मानी हस्तियां और फिल्म स्टार उपस्थित रहे। श्रीमती सीमा सिंह के सुपुत्र श्रेय सिंह और सुपुत्री डॉ मेघना सिंह ने भी उपस्थित लोगों के साथ विभिन्न मुद्राओं में योग किया। भारी संख्या में बुजुर्ग युवा और बच्चे योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, नूपुर सनोन, मिकी मेहता, स्टेनबिन बेन, वीर पढ़ाडिया आदि का समावेश रहा। कुल मिलाकर मेघाश्रेय संस्था द्वारा आयोजित यह एक अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित

पालघर(उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2026 को जिलाधिकारी तथा समिति की अध्यक्ष डॉ. इंदुराणी जाखड़ की अध्यक्षता में तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे की प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति के सभी सदस्य, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। योजना के अंतर्गत पात्र गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण, लंबित मामलों का

निपटारा, लाभ वितरण की गति बढ़ाना, गांव स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाना तथा स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत, आशा स्वयंसेविकाओं एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के समन्वय से पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के संबंध में विभिन्न निर्देश दिए गये। जिलाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड़ ने निर्देश देते हुए कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने गांव स्तर पर विशेष सर्वेक्षण, गृहभेंट एवं जनजागरूकता कार्यक्रम चलाकर योजना की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने हेतु सभी संबंधित यंत्रणाओं को सक्रिय सहभाग सुनिश्चित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

इस बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व्यंकट हुंडेकर, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शशिकांत सालुंखे, सभी चिकित्सा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (नगरीय वसई-विरार पूर्व) गणेश मांटे, बाल विकास परियोजना अधिकारी (पालघर नगरीय) विवेक चौधरी, डहाणू परियोजना अधिकारी सतीश पोल, मनोर परियोजना अधिकारी नाले, पालघर परियोजना अधिकारी अमोल पवार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

भिवंडी में ट्रक समेत 1.90 करोड़ रुपये की गोवा निर्मित शराब जब्त, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, भिवंडी ने ठाणे विभाग के विभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई-नासिक महामार्ग पर वडपे गांव के पास गोवा निर्मित अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ लिया। इस कार्रवाई में 1 करोड़ 63 लाख 29 हजार 600 रुपये मूल्य की विदेशी शराब तथा 27 लाख रुपये मूल्य का कंटेनर समेत कुल 1 करोड़ 90 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गोवा राज्य में बिक्री के लिए निर्मित विदेशी शराब का बड़ा जखीरा कंटेनर क्रमांक लफ61 ऋ1508 के माध्यम से मुंबई-नासिक रोड से ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर विभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार, अधीक्षक उत्तम शिंदे तथा उपअधीक्षक अभिजीत देशमुख के मार्गदर्शन में निरीक्षक सुभाष खंडेराय और दीपक परब के नेतृत्व में विशेष टीम ने वडपे गांव की कमान के समीप जाल बिछाकर निगरानी की। संदिग्ध कंटेनर को रोककर दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेजों में गोवा की कंपनी से राजस्थान के

उदयपुर स्थित एक कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजे जाने का उल्लेख था। हालांकि पंचनामा जांच के दौरान कंटेनर खोलने पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के बजाय रॉयल ब्ल्यू व्हिस्की के 1,620 बॉक्स मिले, जिनमें कुल 77,760 शराब की बोतलें थीं। पुलिस ने कंटेनर चालक हनुमान मोबता राम (28) को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह अवैध शराब गोवा से राजस्थान के उदयपुर ले जाई जा रही थी। मामले की आगे की जांच राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, भिवंडी के निरीक्षक सुभाष एस. खंडेराय कर रहे हैं।

भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी के कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक व पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल पाटिल के हाथों रिबन काटकर किया

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र के वन मंत्री एवं ठाणे जिले के संपर्क मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि भले ही वे पालघर जिले के पालकमंत्री हैं, लेकिन ठाणे जिले के संपर्क मंत्री होने के नाते भिवंडी शहर के विकास पर विशेष ध्यान देंगे और शहर की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। वे भिवंडी महानगरपालिका में भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल, विधायक एडवोकेट माधवी नाईक, विधायक महेश चौघुले, महापौर नारायण चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष रवि सावंत सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। गणेश नाईक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में देश और राज्य विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भिवंडी की शैक्षणिक और नागरिक समस्याओं, विशेष रूप से स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय आम नागरिकों की

समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि भिवंडी में कंक्रीट सड़कों का जाल, मेट्रो परियोजना और 200 बेड के अस्पताल जैसे विकास कार्य भाजपा सरकार की देन हैं। इन परियोजनाओं के लिए महायुति सरकार ने करोड़ों रुपये मंजूर किए हैं। विधायक एडवोकेट माधवी नाईक ने संतोष शेट्टी को जनता का भरोसेमंद चेहरा बताते हुए कहा कि उनके कार्यालय के माध्यम से शहरवासियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम की प्रस्तावना में भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी ने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से नगरसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में आने के बाद उन्हें जनहित के कार्यों को नई दिशा देने का अवसर मिला। उन्होंने पालिका शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का बकाया भुगतान दिलाने के लिए मंत्रालय स्तर पर बैठक आयोजित करने की मांग भी की। महापौर नारायण चौधरी और विधायक महेश चौघुले ने भी गणेश नाईक से भिवंडी के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम में प्रभाग समिति सभापति रजिता मोहन कोंडा, एडवोकेट वैभव भोईर, प्रकाश टावरे, सुमित पाटिल, राजेश शेट्टी, परेश चौघुले, गीता विठोबा नाईक, रोमा निलेश आलशी सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

खावड़ा-महाराष्ट्र बिजली प्रसारण परियोजना से पालघर सहित राज्य की ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में विकसित हो रही खावड़ा अक्षय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित हरित बिजली को महाराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए बनाई जा रही खावड़ा क्ष-उ बिजली प्रसारण परियोजना पालघर जिले सहित पूरे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगी। रेसोनिया लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के तहत पालघर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च-दाब विद्युत लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा।

इस परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड में अतिरिक्त 7 गीगावाट बिजली जोड़ने की क्षमता विकसित होगी। मुंबई महानगर क्षेत्र, पालघर, ठाणे, पुणे तथा महाराष्ट्र के तेजी से बढ़ते औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत प्रसारण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें इस तरह की प्रसारण परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रेसोनिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष निनाद पीतले ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन केंद्र बिजली बनाते हैं, लेकिन उसे घरों, उद्योगों और शहरों तक पहुंचाने का कार्य ट्रांसमिशन नेटवर्क करता है। एक मजबूत और विश्वसनीय प्रसारण व्यवस्था ही ऊर्जा सुरक्षा की असली नींव है।

परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पालघर जिले के ग्रामीणों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है।

साथ ही स्थानीय रोजगार सृजन, कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वृक्षारोपण और हरित विकास गतिविधियों को अपनाया जा रहा है, ताकि परियोजना का विकास सतत और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जा सके।

मीरा-भायंदर मनपा में प्रोटोकॉल उल्लंघन मामला: परिवहन मंत्री के अपमान पर अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर नगर निगम द्वारा आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के मामले ने अब गंभीर प्रशासनिक रूप ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल विभाग ने मामले की जांच के बाद नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 को मीरा-भायंदर पश्चिम में खेल परिसर एवं सभागार भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इस समारोह के निमंत्रण पत्र में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिले के पालक मंत्री प्रताप सरनाईक का नाम प्रोटोकॉल के अनुसार शामिल नहीं किया गया। इसे शासकीय शिष्टाचार और प्रोटोकॉल नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया। इस संबंध में मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद प्रोटोकॉल विभाग द्वारा मामले की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि निमंत्रण पत्र प्रकाशित करने से पहले उसका परीक्षण और स्थानीय उपजिलाधिकारी स्तर पर प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

प्रोटोकॉल विभाग की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के नाम निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रकाशित नहीं किए गए, जिससे शासकीय शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ। रिपोर्ट में इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। मामले में मीरा-भायंदर नगर निगम के आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा नगर अभियंता की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। प्रोटोकॉल विभाग ने ठाणे जिला प्रशासन और मनपा आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की थी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रोटोकॉल विभाग के सचिव एवं मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गावंडे ने शहरी विकास विभाग को पत्र भेजकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि मीरा-भायंदर नगर निगम शहरी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नगर निगम के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले की व्यापक चर्चा हो रही है।

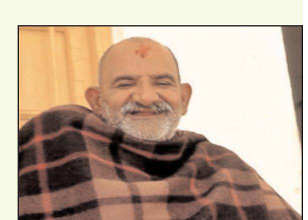

नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालयः
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाप हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाप हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

मुठभेड़ में 50 हजार का इनामिया गो-तस्कर गिरफ्तार, 6 गोवंश और अवैध असलहे बरामद

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जनपद पुलिस ने गो-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामिया गो-तस्कर समेत तीन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह गोवंश, दो अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस तथा तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत थाना रायपुर, पन्नूगंज, कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी/सर्विलांस टीम को सूचना मिली कि गोवंशों से भरी एक पिकअप वाहन बिहार की ओर जा रही है। सूचना पर सारसोत क्षेत्र में घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आरोपी को भी मौके से दबोच लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास यादव, मेराज कुरैशी और विजय प्रताप यादव उर्फ वकील यादव के रूप में हुई है। इनमें विकास यादव पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। तलाशी के दौरान पुलिस ने दो अवैध तमंचे, कारतूस और छह गोवंश बरामद किए।

घायल आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस, आर्म्स एक्ट तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों ने गो-तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी विकास यादव के खिलाफ विभिन्न जनपदों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता पर संयुक्त टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

जम्मू-कश्मीर के किसानों और बागवानों को आयात-निर्यात लाइसेंस देकर अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़े केंद्र सरकार: मोहम्मद अरशद खान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मोहम्मद अरशद खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत किसान यूनियन, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी एवं पूर्व विधायक जौनपुर सदर ने पीडीए भवन, कटघरा, जौनपुर में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में जम्मू-कश्मीर के किसानों, बागवानों और फल उत्पादकों की 25 सूत्रीय समस्याओं और मांगों को देश के सामने रखते हुए प्रधानमंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजने की जानकारी दी।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के किसान, बागवान और फल उत्पादक देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और बागवानी क्षेत्र की रीढ़ हैं, लेकिन आज वे गंभीर आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अव्यवस्था और सरकारी उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में जम्मू-कश्मीर के विकास और किसानों की समृद्धि चाहती है तो उन्हें केवल राहत पैकेज नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के लिए आयात-निर्यात लाइसेंस, आधुनिक भंडारण व्यवस्था और विशेष कृषि नीति प्रदान करनी होगी।

उन्होंने कहा कि सेब, अखरोट, बादाम, चेरी और केसर जैसे उत्पाद विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, लेकिन किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच नहीं मिल पा रही है। बिचौलियों और बड़ी कंपनियों के कारण किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के किसान

उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों और किसान समूहों को सीधे आयात-निर्यात लाइसेंस प्रदान करे, ताकि वे अपने उत्पादों को विश्व बाजार में बेच सकें और बेहतर आय अर्जित कर सकें।

किसानों और बागवानों की प्रमुख समस्याएँ: सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। विदेशी सेबों के आयात से स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (CA Storage) की भारी कमी है। पैकेजिंग सामग्री और कार्टन की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। बागों में रोग और कीट नियंत्रण की लागत अत्यधिक बढ़ गई है। अखरोट, बादाम, चेरी और केसर उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच नहीं है। नकली कश्मीरी केसर के कारण असली उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात सुविधाओं का अभाव है। बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि और बर्फबारी से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। फसल बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं। मंडियों में बिचौलियों का दबदबा बना हुआ है। परिवहन लागत बहुत अधिक है। कृषि ऋण, डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। छोटे और सीमांत किसानों की आय लगातार घट रही है।

भारत किसान यूनियन की प्रमुख मांगें: सेब, अखरोट, बादाम, चेरी और केसर के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। जम्मू-कश्मीर के किसानों और बागवानों को आयात-निर्यात लाइसेंस प्रदान किया जाए। प्रत्येक जिले में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएं। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का 30 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाए। किसानों और बागवानों का सम्पूर्ण कृषि ऋण माफ किया जाए। फल उत्पादकों के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाए। बागवानी फसलों के लिए अलग और प्रभावी बीमा योजना लागू की जाए। किसानों को सस्ती बिजली, खाद, बीज और डीजल उपलब्ध कराया जाए। सेब आयात नीति की समीक्षा कर स्थानीय उत्पादकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक जिले के किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जम्मू-कश्मीर के किसानों और बागवानों की समस्याओं पर विशेष संसद सत्र बुलाया जाए।

मोहम्मद अरशद खान ने घोषणा की कि भारत किसान यूनियन जम्मू-कश्मीर के किसानों, बागवानों, सेब, अखरोट, बादाम, चेरी और केसर उत्पादकों के अधिकारों के लिए व्यापक जनआंदोलन चलाएगी। इसके अंतर्गत किसान पंचायतें, धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन अभियान, जनजागरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों और बागवानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच और सम्मानजनक आय नहीं मिलेगी, तब तक भारत किसान यूनियन उनका संघर्ष पूरे देश में मजबूती से उठाती रहेगी।

बाइक की टक्कर में युवक की मौत, चालक बाइक छोड़कर फरार

केराकत थाना क्षेत्र के लठेपुर प्राथमिक विद्यालय के सामने हुआ हादसा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष पाल (28 वर्ष), पुत्र सियाराम पाल, निवासी मटियारी, थाना केराकत के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संतोष पाल अपनी बहन को कोयलारी से छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 बजे लठेपुर विद्यालय के सामने दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में संतोष पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक अपनी बाइक संख्या यूपी62 एफ 5585 मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

रेलवे अधिकारियों के आश्वासन पर जज सिंह अन्ना ने समाप्त किया आमरण अनशन

जफराबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 का बंद गेट खुला, स्थायी गेट बनाने का मिला आश्वासन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जफराबाद रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर बंद किए गए छोटे गेट को खोलने और भविष्य में स्थायी गेट बनाए जाने के आश्वासन के बाद समाजसेवी जज सिंह अन्ना ने गुरुवार को अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि प्लेटफॉर्म नंबर-4 की ओर से बाहर निकलने वाला छोटा गेट बंद कर दिए जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का

सामना करना पड़ रहा था। शहर की ओर से आने-जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के लिए लगभग दो किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था। इस समस्या को लेकर जज सिंह अन्ना ने बुधवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अनशन की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया। गुरुवार को लखनऊ मंडल के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सीनियर इंजीनियर) सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर बंद किए गए छोटे गेट को खुलवा दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में कार्य विस्तार के दौरान इस स्थान पर स्थायी गेट का निर्माण कराया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के आश्वासन के बाद जज सिंह अन्ना ने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अनशन समाप्त होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और रेलवे प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गेट खुलने से हजारों यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर आरपीएफ के उपनिरीक्षक अजय कुमार, चौकी प्रभारी प्रभुनारायण सिंह, सुमित कुमार, राधेश्याम सिंह, अमूल्य सिंह, विवेकानंद यादव, मनोज मिश्र सहित कई लोग उपस्थित रहे।

गांजा बरामदगी के मामले में पुलिस को झटका

कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर लेने से किया इनकार, अब पीड़ित को मिल रही है धमकी

रियाजुल हक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सरपतहां थाना क्षेत्र में कथित चार किलो गांजा बरामदगी का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए गए आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिलने के बाद अब आरोपी ने पुलिस और कथित गांजा तस्करों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यायालय ने मामले को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर लेने से इनकार कर दिया और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

जानकारी के अनुसार सरपतहां पुलिस ने 15 जून को अखिलेश सिंह नामक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार किलो गांजा बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरफ्तारी और बरामदगी की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए उसे रिमांड पर भेजने से साफ इनकार कर दिया।

रिहा होने के बाद आरोपी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि वह लंबे समय से क्षेत्र में खुलेआम हो रही गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहा था। उसने कथित तौर पर देशी शराब की दुकान के पास हो रही गांजा बिक्री का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। आरोपी का आरोप है कि इसी से नाराज होकर पुलिस और गांजा तस्करों की मिलीभगत से उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके घर के पीछे एक बोरे में गांजा रखवाकर उसे गिरफ्तार किया गया। उसने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया था, जिसे क्षेत्र में लोग वास्तविक गांजा विक्रेता के रूप में जानते हैं। लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया जबकि उसका चालान कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि यदि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती तो असली तस्कर के खिलाफ भी कार्रवाई होती।

आरोपी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमानत पर रिहा होकर घर लौटते समय कथित गांजा तस्कर और थाने के एक हिस्ट्रीशीटर ने उसे गोली मारने की धमकी दी। उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा मुहैया कराने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

उधर न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं पुलिस की ओर से अभी तक आरोपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

फिलहाल कोर्ट के रुख, आरोपी के गंभीर आरोपों और कथित धमकी की घटना ने इस मामले को जिले में चर्चा का विषय बना दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में आखिर कौन सच बोल रहा है और पूरे प्रकरण की वास्तविक तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है।

पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, महिला समेत पूरे परिवार पर हमला

डेढ़ घंटे तक बेहोश रही युवती

प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के खोड़ा गांव में बुधवार शाम पुरानी रंजिश

को लेकर हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पड़ोसियों ने एक महिला, उसकी बेटी, बेटे और पति के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना में 20 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल होकर करीब डेढ़ घंटे तक बेहोश रही।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 7 बजे सविता देवी और पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने सविता देवी के बाल खींचे और उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की।

मां को बचाने पहुंची उनकी 20 वर्षीय बेटी अंशिका को कथित तौर पर पेट में पैर से जोरदार वार किया गया, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ी। परिजनों का कहना है कि अंशिका लगभग डेढ़ घंटे तक बेहोशी की हालत में रही। वहीं 12 वर्षीय सत्यम को थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक दिया गया, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे पिता रविन्द्र कुमार भी हमले में घायल हो गए।

घटना के बाद परिजनों ने एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त होने पर मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल घटना के बाद गांव में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है, जबकि पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

भय के साये में जी रहा दिव्यांग परिवार, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खुटहन थाना क्षेत्र के सैद पनौली गांव निवासी संगीता पत्नी संतलाल ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय की मांग की है। संगीता का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग लंबे समय से उनके परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। पीड़िता के अनुसार उनके पति संतलाल शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तथा बीमारी के चलते उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में परिवार पहले से ही आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से जूझ रहा है। आरोप है कि पड़ोसी आए दिन घर पहुंचकर गाली-

गलौज करते हैं और गांव छोड़ने की धमकी देते हैं। संगीता ने बताया कि मामले की शिकायत कई बार थाना खुटहन और क्षेत्राधिकारी शाहगंज से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायत करने पर विपक्षी पक्ष और अधिक आक्रामक हो जाता है तथा रास्ते में रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि भय और असुरक्षा के माहौल में परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इस मामले ने ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और पीड़ित परिवार को कब तक राहत मिलती है।

नोट: समाचार में उल्लिखित सभी आरोप पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र पर आधारित हैं। आरोपित पक्ष का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी

होम्योपैथिक शिविर में स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक

प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रेक्षागृह में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई।

इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह ली और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। शिविर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) डॉ. अजय श्रीवास्तव ने खसरा और चेचक जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए समय पर उपचार और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों

के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें मरीजों को निशुल्क प्रदान किया जाता है।

डॉ.श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में सरकारी चिकित्सालयों की सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा समय रहते चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें।

प्रदर्शनी में आए लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की पहल की सराहना करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं और चिकित्सा सेवाओं की जानकारी हासिल की। स्वास्थ्य जागरूकता के साथ-साथ यह प्रदर्शनी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम साबित हुई।

गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों लोगों की सुनी गई समस्या, निस्तारण करने का दिया निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद के सिरकोनी विकास खण्ड के कादीपुर गांव में विशेष जन संपर्क एवं जन जागरूकता अभियान के

तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सरकार के द्वारा किया गया विकास कार्यों के बारे में जानकारी दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर हरेन्द्र सिंह ने चौपाल लगाकर सरकार के योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। सभी ग्रामीणों की समस्या को सुनते

पुर्व विधायक हरेन्द्र सिंह ने एक-एक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए तहसील या ब्लॉक के चक्कर न काटने पड़ें। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायत में चौपाल लगाने का कार्यक्रम कर रहा है।

चौपाल के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का रैंडम सर्वे कराया गया। सर्वे में पात्र पाए गए लोगों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन,आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाया गया।ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या ग्रामीणों ने प्रमुखता से उठाई। कई मजरों में हैंडपंप खराब होने और पाइपलाइन न पहुंचने की शिकायत की गई। विधायक ने इसे गंभीरता से लेते हुए जल निगम विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चौपाल में ग्राम प्रधान,लेखपाल, पंचायत सचिव,जल निगम और अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।कार्यक्रम के अंत में विधायक ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि चौपाल का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है।

10 बसों का चालान, 03 बसें सीज

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों तथा अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सत्येन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में यात्री/मालकर अधिकारी प्रमोद कुमार के साथ बीती रात्रि जनपद के विभिन्न मार्गों पर सघन जांच अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान लगभग 50 बसों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना नम्बर प्लेट, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 10 बसों का चालान किया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 03 बसों को संबंधित थानों में सीज कर दिया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सत्येन्द्र कुमार सिंह ने वाहन संचालकों से यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जनसुरक्षा के दृष्टिगत ऐसे विशेष अभियान आगे भी निरंतर चलाए जाते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण

रेणुकोट,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंडालको कॉलोनी सेकंड प्लांट स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह आश्रम, शाखा रेणुकोट परिसर में वृक्षारोपण किया।

इस अवसर पर जिला कार्यसमिति सदस्य राज वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मातृ सम्मान का भी संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी मां के नाम एक पौधा लगाए और उसका संरक्षण करे तो देश का हरित आवरण बढ़ाने में बड़ी सफलता मिल सकती है। यह अभियान पारिवारिक मूल्यों और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। वहीं निवर्तमान जिला संयोजक भाजपा आईटी विभाग अभय सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में तेजी से घटते हरित क्षेत्र और बढ़ते पर्यावरणीय संकट को देखते हुए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में आश्रम की व्यवस्थापक मदन सिंह, मंडल उपाध्यक्ष प्रेम शंकर रावत, दुर्ग विजय मिश्रा, राजेश चौधरी, धर्मेंद्र शर्मा, सुधांशु चौहान, गणेश चौहान, अरुण सिंह, अनूप केशरी, आनंद अग्रहरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

अज्ञात शव की खबर प्रकाशित होते ही हरकत में आई बदलापुर पुलिस, सातवें दिन हुआ पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला चिकित्सालय के शवगृह में पिछले छह दिनों से पड़े एक अज्ञात व्यक्ति के शव को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के सीमा विवाद में मामला उलझा रहने के कारण शव का समय पर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं हो सका। इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आवश्यक कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल के शवगृह में एक अज्ञात व्यक्ति का शव कई दिनों से रखा हुआ था। शव के सड़ने की स्थिति बनने लगी थी, लेकिन संबंधित पुलिस थाने द्वारा समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। मामला मीडिया में आने और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पहुंचने के बाद बदलापुर पुलिस सक्रिय हुई बताया जाता है कि बुधवार देर रात बदलापुर पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और शव को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ की व्यवस्था कराई। गुरुवार दोपहर हेड कांस्टेबल नागेंद्र कुमार ने शव को कफन में लपेटकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रामघाट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जिला अस्पताल के शव रजिस्टर में मृतक का नाम रंजय दुबे (लगभग 40 वर्ष) निवासी पूर्वा, मोतीहारी (बिहार) दर्ज था। इसके बावजूद उसकी शिनाख्त और परिजनों तक सूचना पहुंचाने में सफलता नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस प्रारंभ से ही गंभीरता दिखाती तो मृतक की पहचान और परिजनों का पता लगाने की संभावना बढ़ सकती थी। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों में जिम्मेदारी निभाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि मानव शव के प्रति बरती गई लापरवाही से व्यवस्था की संवेदनहीनता उजागर हुई है।

नाबालिग पीड़िता के मेडिकल में लापरवाही का आरोप, जिला अस्पताल का वीडियो वायरल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला अस्पताल में एक नाबालिग पीड़िता के मेडिकल परीक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पीड़िता के परिजनों, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों के बीच मेडिकल परीक्षण को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचने के बावजूद डॉक्टरों ने मेडिकल करने में अनावश्यक देरी की। उनका कहना है कि पहले यह लिखवाने का प्रयास किया गया कि पीड़िता मेडिकल नहीं कराना चाहती, जबकि लड़की स्वयं मेडिकल कराने की इच्छा जता रही थी। परिजनों के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद मेडिकल करने की बात तो कही गई, लेकिन बाद में स्टाफ की कमी का हवाला देकर घंटों इंतजार कराया गया। उनका आरोप है कि करीब दो से तीन घंटे तक अस्पताल में बैठाए रखने के बाद उन्हें अगले दिन आने के लिए कह दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल में अन्य लोगों के मेडिकल परीक्षण किए जा रहे थे, फिर भी पीड़िता के मामले में देरी की गई। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले को लेकर परिजनों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर संबंधित डॉक्टरों की भूमिका की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मेडिकल परीक्षण में हुई देरी से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वहीं, जब इस संबंध में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) से संपर्क किया गया तो उन्होंने विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित चिकित्सक ही पूरे मामले की जानकारी दे सकते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि संवेदनशील मामलों में मेडिकल परीक्षण जैसी जरूरी प्रक्रिया में देरी गंभीर चिंता का विषय है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

इनब्रू बेवरेजेज ने लॉन्च की रोमानोव जैजी जामुन मिंट वोडका

मुंबई। भारत के सबसे पसंदीदा वोडका ब्रांड्स में से एक, रोमानोव वोडका, ने महाराष्ट्र में रोमानोव जैजी जामुन मिंट वोडका लॉन्च कर अपने सबसे दमदार फ्लेवर इनोवेशन का अनावरण किया है। जामुन के समृद्ध और परिचित स्वाद को ताजगीभरे मिंट फिनिश के साथ जोड़ते हुए, यह नया वैरिएंट ब्रांड के फ्लेवर्ड वोडका पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है और आज के उपभोक्ताओं के लिए, नए फ्लेवर अनुभव तैयार करने की रोमानोव की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह लॉन्च उभरती उपभोक्ता पसंदों को पहचानने और उन्हें आधुनिक एवं प्रासंगिक उत्पादों में बदलने पर रोमानोव के निरंतर फोकस को दर्शाता है। जैसे-जैसे उपभोक्ता अनूठे फ्लेवर और अलग तरह के ड्रिंकिंग अनुभवों की तलाश कर रहे हैं, रोमानोव सांस्कृतिक जुड़ाव और आधुनिक स्वादों के संतुलन के साथ अपने मजबूत इनोवेशन पाइपलाइन के माध्यम से बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉन्च के अवसर पर इनब्रू बेवरेजेज के जनरल मैनेजर - मार्केटिंग, सुमित तिवारी ने कहा, रोमानोव ने महाराष्ट्र में दशकों से वोडका श्रेणी का नेतृत्व किया है और बोल्ड, युवा तथा सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव रखने वाले फ्लेवर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाया है।

जामुन मिंट के साथ हम एक ऐसा विशिष्ट फ्लेवर कॉम्बिनेशन पेश कर रहे हैं जो परिचित स्वाद और ताजगी का बेहतरीन मेल है, और आज के उपभोक्ताओं के लिए एक आधुनिक ड्रिंकिंग अनुभव प्रदान करता है। रोमानोव जैजी जामुन मिंट वोडका अब महाराष्ट्र भर में 750 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. और 90 मि.ली. पैक साइज में उपलब्ध है।

डेढ़ माह बाद फिर फूटा आक्रोश, दूल्हा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा परिवार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। चर्चित दूल्हा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मृतक के परिजनों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर दिखाई दिया। घटना के करीब डेढ़ माह बाद परिजनों और समर्थकों ने सद्भावना पुल से कलेक्ट्रेट तक न्याय मार्च निकालकर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और शीघ्र न्याय की मांग की। इस दौरान मृतक की बहन सौम्या बिंद आंदोलन का नेतृत्व करती नजर आईं। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने ₹भाई के हत्यारों को सजा दो₹ और ₹हमें न्याय चाहिए₹ जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। परिजनों का आरोप है कि घटना को काफी समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक संतोषजनक न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की मांग की सौम्या बिंद ने कहा कि उनका परिवार लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। न्याय मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन परिजनों की पीड़ा और आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब इस मामले में प्रशासन और जांच एजेंसियों की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में लगातार आवाज बुलंद कर रहा है।

भावेश बायेती ने सीए परीक्षा उत्तीर्ण कर बढ़ाया गौरव

मुंबई। विक्रोली पार्कसाइट स्थित महेश ज्वेलर्स के संचालक एवं श्री ॐ नारायण सत्संग मंडल के सक्रिय सहयोगी महेश बायेती के सुपुत्र भावेश बायेती ने प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर परिवार, समाज एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भावेश की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर परिवारजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों में हर्ष का वातावरण है। ॐ श्री नारायण सत्संग मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अरविंद शुक्ला, प्रो. अभयकांत तिवारी, अजय पांडेय, दिनेश सिंह, निलेश तिवारी, विशेष कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र शासन एवं पत्रकार आदेश मिश्र, अश्विनी लांजेकर, पंडित मधुसूदन उपाध्याय, सुनील ठाकुर, सुमित पांडेय सहित अनेक शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भावेश बायेती को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

वन डे गवर्नेंस शिविर में 2007 आवेदनों का निस्तारण, लोगों को मिला योजनाओं का लाभ

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से गुरुवार को तहसील केराकत तहसील सभागार में ₹वन डे गवर्नेंस₹ शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी गईं तथा मौके पर ही अनेक मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर के दौरान विकास विभाग ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों में 84 जन्म प्रमाण पत्र एवं 41 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए। नगर पंचायत द्वारा 17 जन्म प्रमाण पत्र तथा 4 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग ने 3 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री हेतु ई-केवाईसी कराया तथा 5 किसानों को बाजरा मिनी किट वितरित की। समाज कल्याण विभाग ने 3 वृद्धजनों एवं 2 पेंशनधारकों का आधार ई-केवाईसी कराया। विद्युत विभाग को प्राप्त 9 शिकायतों में से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। पूर्ति विभाग ने 3 अन्त्योदय तथा 12 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी किए।

राजस्व विभाग द्वारा भी शिविर में व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान की गईं। विभाग ने 1417 आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी किए। इसके अलावा 263 वरासत, 143 खतौनी संबंधी त्रुटि सुधार तथा 5 कृषि दर्ज मामलों का निस्तारण किया गया। ग्राम गोंइठा में नवीन पैमाइश और ग्राम पेसारा में सड़क पर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई भी की गई। ग्राम पेसारा और कुण्डी के प्रधानों के प्रार्थना पत्रों पर चकरोड की पैमाइश कराई गई।

उपजिलाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शिविर के माध्यम से कुल 2007 आवेदनों का निस्तारण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया उपजिलाधिकारी सुनील कुमार कि अध्यक्षता में चले इस कार्यक्रम में विकास विभाग पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर लोहिया पार्क में आयोजित हुआ विशेष योग सत्र

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शासन की मंशानुरूप जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. एवं मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अंतर्गत चल रहे योग सप्ताह के चौथे दिवस पर लोहिया पार्क में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के साथ विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने योग को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि योग स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी लोगों से नियमित योगाभ्यास अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. कमल रहे। योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. सुशील अग्रहरि ने एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि साथ रहने, भोजन करने अथवा सामान्य संपर्क से एचआईवी संक्रमण नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि संतुलित जीवनशैली, पौष्टिक आहार, नियमित योग, ध्यान एवं प्राणायाम के साथ चिकित्सकीय परामर्श एवं एआरटी उपचार अपनाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तथा जीवन को स्वस्थ एवं बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने मत्स्यासन, सिंहासन, ताड़ासन, वक्रासन, सूर्य नमस्कार, ध्यान एवं प्राणायाम के स्वास्थ्य लाभों की भी जानकारी दी। पतंजलि योग समिति उत्तर प्रदेश के सह राज्य प्रभारी अचल हरीमूर्ति एवं मुख्य योग शिक्षक अरविंद कुमार द्वारा प्रतिभागियों को विभिन्न योग क्रियाओं एवं प्राणायामों का अभ्यास कराया गया। इस दौरान भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी एवं उद्गीथ प्राणायाम के साथ ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया। बताया गया कि सूर्य नमस्कार किसी एक आसन का नाम नहीं, बल्कि विभिन्न योगासनों का समन्वित समूह है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर के सभी तंत्रों को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सूर्य नमस्कार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, रक्त संचार को संतुलित रखने तथा शरीर में प्राणवायु के प्रवाह को बेहतर बनाने में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। विशेषज्ञों ने सभी लोगों से अपनी क्षमता एवं स्वास्थ्य के अनुरूप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने बढाई इन-सर्विस शिक्षको के लिए टीईटी योग्यता प्राप्त करने की सीमा,

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यरत शिक्षकों के टीईटी/सीटीईटी संबंधी विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग अवदेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका संख्या 53434/2025, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट में 29 मई 2026 को पारित आदेश के तहत इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.86 लाख शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। ये शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, इनमें लगभग 50 हजार शिक्षक ऐसे हैं, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अभाव में टीईटी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे। ऐसे शिक्षकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानकों में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही उनके लिए एक विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

तत्कालीन थानाध्यक्ष अश्विनी दूबे सहित दो पुलिस अधिकारियों को नोटिस

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। लगभग दो वर्ष पहले पत्रकार के साथ बदतमीजी करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये भारतीय प्रेस परिषद गम्भीर हो गया। इतना ही नहीं, परिषद ने महाराजगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अश्विनी दूबे और उपनिरीक्षक एसपी पाण्डेय को नोटिस भी जारी कर दिया है। परिषद ने दोनों पुलिस अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर लिखित जवाब मांगा है, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिये बाध्य हो जायेगा। प्रेस परिषद की सचिव शुभा गुप्ता द्वारा 5 जून को जारी नोटिस (केस संख्या 157/2024/बीपीसीआई) के अनुसार पत्रकार पंकज कुमार ने महाराजगंज थाने के उपरोक्त दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। शिकायत में उन पर पत्रकार को धमकाने और प्रेस की स्वतंत्रता में कथित तौर पर बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। प्रारम्भिक जांच के बाद प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने पाया कि यह मामला ₹प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण/कुठाराघात प्रतीत होता है₹। इसके बाद परिषद ने प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13(1) और धारा 15(4) के तहत कार्यवाही की चेतावनी देते हुये दोनों पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है। परिषद ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नोटिस मिलने के 14 दिन के भीतर अपना लिखित वक्तव्य 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें। इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता पत्रकार पंकज कुमार को भी भेजनी होगी। निर्धारित समय में जवाब न देने की स्थिति में यह मामला परिषद की जांच समिति के समक्ष पेश किया जायेगा और उचित आदेश पारित किया जायेगा। वहीं परिषद द्वारा की गयी इस कार्यवाही से पत्रकार संगठनों का कहना है कि यह कदम प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। महाराजगंज क्षेत्र में इस नोटिस के बाद पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत सरकार के सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद के प्रेक्षागृह में तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। यह प्रदर्शनी 5 जून से 21 जून तक संचालित समेकित जनकल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव, विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ह्यप्रिंसूह्ल, पूर्व विधायक बाकेलाल सोनकर, जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. तथा मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा स्थापित ह्यसेल्फी विद पीएमह्ल सेल्फी प्वाइंट आकर्षण का केंद्र रहा। प्रदर्शनी में बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया तथा अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने आगंतुकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और प्रचार सामग्री वितरित की।

अपने संबोधन में राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीबों, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों को व्यापक लाभ मिला है। उन्होंने जनपद में चल रहे ओवरब्रिज, पुल, रिंग रोड, स्वास्थ्य सुविधाओं और खेल अवसंरचना से जुड़े विकास कार्यों की भी जानकारी दी। एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए जनभागीदारी आवश्यक है।

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड, टूलकिट एवं सांकेतिक चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत शत्रुघ्न सोनकर एवं सौरभ मिश्रा को पांच-पांच लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत अमन अली एवं शैलेन्द्र निषाद को टूलकिट वितरित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंजीकृत कलाकारों और बेसिक शिक्षा विभाग की छात्राओं ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में रंगारंग माहौल बनाया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सड़क दुर्घटना में युवक की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में पसरा मातम

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। स्थानीय क्षेत्र के लठ्ठेपुर प्राथमिक विद्यालय के समीप बुधवार की देर शाम उस समय सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जब युवक अपनी बहन को रिश्तेदारी छोड़ वापस अपने घर लौट रहा था, मृतक की पहचान संतोष पाल पुत्र स्व. सियाराम पाल 28वर्ष निवासी मटियारी गांव के रूप में हुई। विदित हो कि संतोष पाल अपनी बहन सोनी पाल को डोभी क्षेत्र स्थित कोइलारी गांव में छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था जैसे ही वह लठ्ठेपुर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप पहुंचा तभी बेलाव से केराकत की तरफ आ रही तेज रफ्तार बाइक विपरीत दिशा में जाकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही संतोष पाल सड़क के किनारे बेसुध होकर जा गिरा, टक्कर की आवाज सुन आस-पास के लोगो की भीड़ इकट्ठा होकर घायल के उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वही भीड़ का फायदा उठाकर बाइक सवार मौके पर बाइक छोड़ फरार हो गया, मौत की खबर होते ही परिवार में कोहराम मच गया परिजनों की चीख-पुकार सुन मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक संतोष पाल चार बहनों में इकलौता था, विगत 20 वर्ष पूर्व पिता का साया सर उठ गया था, माता प्राथमिक विद्यालय में रसोइया का काम करती है छोटी सी उम्र से ही पढ़ाई के साथ - साथ होम ट्यूशन कर परिवार का भरण पोषण भी करता था। अब संतोष की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट का बोझ मंडरा रहा है। मृतक के चचेरे भाई अरविंद कुमार पाल ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वही मृतक के पोस्मार्टम के बाद अंतिम संस्कार बेलाव स्थित घाट पर किया गया।

डेढ़ माह बाद फिर फूटा आक्रोश, दूल्हा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा परिवार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। चर्चित दूल्हा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मृतक के परिजनों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर दिखाई दिया। घटना के करीब डेढ़ माह बाद परिजनों और समर्थकों ने सद्भावना पुल से कलेक्ट्रेट तक न्याय मार्च निकालकर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और शीघ्र न्याय की मांग की।

इस दौरान मृतक की बहन सौम्या बिंद आंदोलन का नेतृत्व करती नजर आईं। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने ₹भाई के हत्यारों को सजा दो₹ और ₹हमें न्याय चाहिए₹ जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

विद्यालय के बच्चों ने किया योगाभ्यास, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए किया गया पूर्वाभ्यास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत जनपद के प्रेक्षागृह में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के सफल आयोजन हेतु योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास कराया गया।

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को योग प्रशिक्षक अचल हरीमूर्ति द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। उन्होंने सहज एवं सरल व्यायामों के साथ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में त्रिकोणासन, वृक्षासन, पादहस्तासन एवं अर्धचक्रासन का अभ्यास कराया तथा इनसे होने वाले शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रेरणा गीत का सामूहिक गायन किया गया तथा सभी ने उत्साहपूर्वक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर प्रेक्षागृह में उच्च प्राथमिक विद्यालय कबिरुद्दीनपुर के छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न योगासनों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों ने बकासन, चक्रासन, पादहस्तासन, उत्तानपादासन, शशकासन एवं गोमुखासन सहित भ्रामरी तथा उद्गीथ प्राणायाम का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने योग को स्वस्थ जीवनशैली का आधार बताते हुए नियमित रूप से योग अपनाने का संकल्प लिया।

ठाणे में ज्येष्ठ नागरिक कट्टा का शुभारंभ संपन्न

ठाणे। गुरुवार को ठाणे स्थित रेसिडेंसी यूको बैंक के सामने आनंद नगर स्वास्तिक ज्येष्ठ नागरिक कट्टा का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिवगर्जना प्रतिष्ठान एवं ज्येष्ठ नागरिक कट्टा के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन शिवगर्जना प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विशाल तरे, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा के संस्थापक संजय जाम्बावलिकर तथा विशेष अतिथि नरेश मणेरा के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि ज्येष्ठ नागरिक समाज के अनुभव और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। ऐसे मंच वरिष्ठ नागरिकों को एक-दूसरे से जोड़ने, उनके विचारों के आदान-प्रदान तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम में समाजसेवी विजय मिश्रा सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठजन उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाजहित में एक सराहनीय कदम बताया।

भारत के जलवायु एवं सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशन इकोसिस्टम को सशक्त बनायेंगे ईकोहब.इन

मुंबई। री-सस्टेनेबिलिटी की सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव पहल रेज़िलिएंस एक्शंस ने ईकोहब.इन नामक एक स्टेबिलिटी-केंद्रित इनक्यूबेटर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु एवं क्लीन-टेक, प्रदूषण प्रबंधन, संसाधन दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा सतत नवाचार के क्षेत्र में कार्यरत शुरूआती चरण के उद्यमों को समर्थन प्रदान करना है। यह पहल उन स्टार्टअप्स के लिए तैयार की गई है जो आइडिएशन चरण से आगे बढ़ चुके हैं और व्यावसायिक स्तर पर विस्तार के लिए तैयार हैं। इनके पास कार्यशील मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (एमवीपी), समर्पित टीम और स्पष्ट रूप से परिभाषित बाजार अवसर होना आवश्यक है। मसूद मलिक, प्रबंध निदेशक - समूह सीईओ, री सस्टेनेबिलिटी ने कहा, भारत का स्थिरता परिवर्तन केवल बुनियादी ढांचे के माध्यम से संचालित नहीं होगा। यह नवाचार, उद्यमिता और उन विचारों को बड़े स्तर पर लागू करने की क्षमता से संचालित होगा जो वास्तविक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। ECO-HUB.IN के माध्यम से हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जो नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, शिक्षाविदों और नीति निमार्ताओं को एक साथ लाकर ऐसे समाधानों को गति देगा जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और मापनीय प्रभाव देने में सक्षम हों।

जैसे-जैसे भारत कम-कार्बन, सर्कुलर और लचीली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वैसे-वैसे नवाचारी स्थिरता समाधानों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। देशभर के उद्यमी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाली नई तकनीकों और कारोबारी मॉडलों का विकास कर रहे हैं, लेकिन मेंटरशिप, गैर-इक्विटी उत्प्रेरक पूंजी, उद्योग साझेदारियों, पायलट अवसरों और व्यवसाय सत्यापन तक सीमित पहुंच के कारण उन्हें विस्तार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईकोहब.इन की स्थापना इन कमियों को दूर करने और उच्च क्षमता वाले स्थिरता उद्यमों को ऐसे स्के-लेबल व्यवसायों में बदलने के लिए की गई है, जो मापनीय पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव प्रदान कर सकें।

पत्रकारिता समाज का आईना, सत्य की मशाल कभी बुझनी नहीं चाहिए : डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु'

-सुरेश गांधी

वाराणसी. पत्रकारिता केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि समाज के अंतर्मन का दर्पण है। सत्य को निर्भीकता से सामने लाने और जनभावनाओं को स्वर देने की परंपरा ही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है। काशी की धरती ने ऐसी ही मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को जन्म दिया है, जिसने समय-समय पर समाज को दिशा और राष्ट्र को नई चेतना प्रदान की। इसी गौरवशाली परंपरा के प्रतीक पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार एवं कॉन्फ्रेंस हॉल के सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने किया।

अपने विधायक निधि से कराए गए इस कार्य का लोकार्पण करते हुए डॉ. मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों ने सदैव सत्ता और समाज के बीच सेतु बनकर जनभावनाओं को स्वर दिया है। सत्य की खोज, जनसरोकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में पत्रकारों की भूमिका सदैव प्रेरणादायी रही है।

उन्होंने कहा कि पराड़कर स्मृति भवन केवल एक भवन नहीं, बल्कि भारतीय पत्रकारिता की उस गौरवशाली विरासत का जीवंत स्मारक है, जिसने अनेक पीढ़ियों को वैचारिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया। इस धरोहर का संरक्षण और विकास करना समाज के प्रति हम सभी का दायित्व है।

काशी ने मुझे बनाया, इसलिए यह मेरा दायित्व है

भावुक अंदाज में मंत्री ने कहा कि उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन काशी की मिट्टी से जुड़ा है। छात्र जीवन, शिक्षक जीवन और सार्वजनिक जीवन–हर पड़ाव पर काशी ने उन्हें पहचान दी। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब इसी सभागार की बुकिंग कराने तक के लिए संसाधन जुटाने पड़ते थे, लेकिन आज उसी भवन के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। यह उनके लिए सौभाग्य और ईश्वर की कृपा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुंदरीकरण के कुछ कार्य तकनीकी एवं बजटीय कारणों से शेष रह गए हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा कराया जाएगा। 'यह मेरा नहीं, समाज का धन है और समाज के हित में ही खर्च होगा' उन्होंने भरोसा दिलाया कि भवन की अन्य आवश्यकताओं को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

विद्यालय, मंदिर, अस्पताल और पत्रकार भवन भी विकास की प्राथमिकता

डॉ. मिश्र ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका प्रयास केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर उपयोगी संस्थान को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अपनी विधायक निधि से अनेक विद्यालयों में स्टेनलेस स्टील के बड़े वाटर कूलर लगाए गए हैं, सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइटें स्थापित कराई गई हैं तथा मंदिरों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराड़कर स्मृति भवन भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कोई मंदिर या सार्वजनिक सेवा का केंद्र।

भाजपा में कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि

अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा ने एक सामान्य कार्यकर्ता को विधायक और फिर मंत्री बनाकर यह सिद्ध किया है कि इस दल में कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जो भी दायित्व मिला है, वह समाज की सेवा के लिए मिला है और वे इसे पूरी निष्ठा से निभाते रहेंगे।

सरकारी सहायता अब पहले से अधिक सरल और त्वरित

उन्होंने कहा कि पहले गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना बेहद कठिन था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और तेज हो गई है। अब जरूरतमंदों को कम समय में सहायता उपलब्ध हो रही है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है।

पत्रकारों के हित सरकार की प्राथमिकता

डॉ. मिश्र ने कहा कि पत्रकार कठिन परिस्थितियों में दिन-रात कार्य करते हैं और समाज के सामने सत्य लाने का दायित्व निभाते हैं। सरकार पत्रकारों के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है तथा इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश सरकार की विकासपरक नीतियों के कारण आज काशी वैश्विक पहचान बना रही है। पराड़कर स्मृति भवन का सुंदरीकरण भी उसी विकास यात्रा का हिस्सा है, जो पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम बनेगा।

कार्यक्रम में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने संघ को वाटर कूलर उपलब्ध कराने में सहयोग देने वाले मालवीय मार्केट व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों अभिषेक केसरी, विनय अरोड़ा, ऋषि आहूजा एवं गुरमीत सिंह बग्गा को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने तथा आभार ज्ञापन कोषाध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने किया। समारोह में संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अत्रि भारद्वाज, पूर्व महामंत्री अखिलेश मिश्र, उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, कैलाश यादव, प्रेस क्लब अध्यक्ष चंदन रुपानी, विनय शंकर सिंह, अजय राय, अश्वनी श्रीवास्तव, सुरेश गांधी, विजय शंकर गुप्ता, शैलेन्द्र भारती, राजेंद्र यादव, सुशील मिश्र, राजेश यादव, डॉ. जिग्नेश कुमार, आशुतोष पांडेय, राजेश सेठ, हरिमोहन श्रीवास्तव 'अन्नू', रवीन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, मुन्नालाल साहनी, कौसर अली कुरैशी, मनोज राय, डॉ. रजनीश सिंह, मोहम्मद इमरान, चंद्र प्रकाश मिश्रा, अशफाक सिद्दीकी, दिलीप कुमार, ओंकार तिवारी, रोहित सोनकर, बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, चंद्रप्रकाश 'चंदू' सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पत्रकार को धमकाने के मामले में एडवोकेट रिवाज खलील ने भेजा कानूनी नोटिस

लाल शेखर सिंह

प्रतापगढ़/मुंबई (उत्तरशक्ति)। अमृत प्रभात एनआईपी दैनिक के उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला प्रभारी एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा की ओर से अधिवक्ता रिवाज खलील ने मरोल चर्च रोड स्थित जूस सेंटर संचालक शिवान तेवर को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि झूठी एवं भ्रामक अफवाहों के आधार पर शिवान तेवर ने मरोल नाका, अंधेरी पूर्व स्थित पत्रकार के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उनके पुत्र को कथित रूप से धमकी दी। अधिवक्ता द्वारा भेजे गए नोटिस में इस कृत्य को गंभीर बताते हुए इसे कानून एवं नागरिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है।

एडवोकेट रिवाज खलील ने नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में पत्रकार या उनके परिवार के प्रति किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न अथवा मानहानिकारक गतिविधि की गई तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। पत्रकार राजेश शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और किसी भी पत्रकार को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने या भय का वातावरण बनाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून पर उनका पूरा विश्वास है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्य सामने आएगा। यह मामला अब कानूनी दायरे में पहुंच चुका है और पत्रकार जगत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। संबंधित पक्षों की ओर से आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

मंगेश कुडाळकर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं

मुंबई। कुर्ला विधानसभा के आमदार मंगेश कुडाळकर के जन्मदिन के अवसर पर बालासाहेब ठाकरे नगर, नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं समर्थकों ने उन्हें शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में समाजसेवक सुखबिन्दर सिंह (लाला भाई) सहित अनेक नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मंगेश कुडाळकर जी के उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कीं। अपने जन्मदिन पर मिले स्नेह और सम्मान के लिए मंगेश कुडाळकर जी ने सभी अतिथियों एवं शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मेहमानों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई, जिसका सभी ने आनंद लिया। यह आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लेकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

डुमना चैरिटेबल ट्रस्ट ने नगरसेविका अपर्णा पाटील के हाथों कराया नोटबुक वितरण

मानिकपुर (उत्तरशक्ति)। डुमना चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निर्मला माता प्राइमरी स्कूल, मानिकपुर (वसई वेस्ट) में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री के रूप में नोटबुक वितरित की गईं। इस अवसर पर वसई-विरार महानगरपालिका की नगरसेविका अपर्णा पाटील ने विद्यार्थियों को नोटबुक प्रदान कीं। इस अवसर पर अपर्णा पाटील ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव भी है। विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक यात्रा में प्रोत्साहित करने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके सपनों को नई दिशा देने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। नगरसेविका अपर्णा पाटील ने इस सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी और उत्साह ऐसे प्रयासों के महत्व को और बढ़ा देते हैं। कार्यक्रम में सिस्टर स्टेविना लोपिस, डुमना चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन उस्तेस सिकवेरा, वसई की विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित, कॉर्पोरेटर श्रीमती निम्मी निपुण दोशी, कल्पेश पांडे, रिचर्ड दादा, मनोज गुप्ता तथा हरीश बेदी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आयोजकों ने कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की रचनात्मक एवं समाजोपयोगी पहल जारी रखी जाएंगी।

पार्लियामेंटरी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले सांसद डॉ. हेमंत सावरा

मुंबई। पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत सावरा ने पार्लियामेंटरी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।

बैठक में आदिवासी एवं दूर-दराज के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए संचालित पार्लियामेंटरी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा की गई। इस परियोजना को महाराष्ट्र में सकारात्मक प्रतिसाद मिला है, जिसके बाद इसे अब विधानसभा क्षेत्रों तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 गांवों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इनमें महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, युवाओं के कौशल विकास तथा रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में सांसद डॉ. हेमंत सावरा के साथ योजना सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार, पूर्व सांसद हीना गावित तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सांसद डॉ. सावरा ने कहा कि यह पहल ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के सतत एवं समावेशी विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

FNP ने फादर्स डे 2026 कलेक्शन हीज द रीजन लॉन्च किया

मुंबई। भारत के अग्रणी गिफ्टिंग ब्रांड FNP (Fer»»fs N PetÔls) ने इस वर्ष फादर्स डे के अवसर पर हीज द रीजन अभियान के तहत एक विशेष गिफ्टिंग कलेक्शन लॉन्च किया है। यह थीम हमारे जीवन, संस्कारों और मूल्यों को आकार देने वाली पिताओं की मूक शक्ति के प्रति सम्मान और अनकहा आभार व्यक्त करती है। पारंपरिक उपहारों से आगे बढ़कर इस कलेक्शन के प्रत्येक उत्पाद को भावनाओं, यादों और व्यक्तिगत जुड़ाव की अभिव्यक्ति के रूप में तैयार किया गया है। कलेक्शन में आकर्षक फ्लोरल अरेंजमेंट्स, पौधे, गॉरमेट हैम्पर्स, एक्सेसरीज और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स (जैसे फोटो मग, एलईडी लैंप) शामिल हैं। इस कलेक्शन की मुख्य विशेषता FNP की विशेष 'ब्लू-थीम्ड फ्लोरल रेंज' (जैसे- द ब्लू क्लासिक ट्रिब्यूट, डैड्स ब्लू स्माइल) है, जो पितृत्व के गुणों जैसे शक्ति और भरोसे का प्रतीक है। इसके अलावा, प्रीमियम अनुभव के लिए 'FNP Luxe' के तहत आर्टिजनल केक्स और विशेष गिफ्ट सेट्स (जैसे- द गिल्डेड जेंटलमैन, ब्लू वेलवेट) भी पेश किए गए हैं। उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलावों को देखते हुए FNP ने पाया है कि लोग अब केवल उत्पाद नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और कहानी बयां करने वाले उपहार पसंद कर रहे हैं। 249 रुपये से 9,000 रुपये तक की विभिन्न मूल्य श्रेणियों में उपलब्ध यह कलेक्शन आम ग्राहकों के साथ-साथ कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सॉल्यूशंस भी प्रदान करता है, जिसे FNP की भरोसेमंद डिलीवरी सेवाओं के जरिए आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए FNP के सीएमओ अवि कुमार ने कहा, फादर्स डे एक ऐसा अवसर है जो हमें पिता के मौन समर्पण, उनकी ताकत और अटूट सहयोग का सम्मान करने का मौका देता है। हीज द रीजन के माध्यम से हम उस भावना को सामने लाना चाहते थे, जो हर व्यक्ति के दिल से जुड़ती है—यह स्वीकार करना कि हमारे जीवन के कई मूल्य, यादें और उपलब्धियाँ हमारे पिता की वजह से संभव हुई हैं। यह कलेक्शन ग्राहकों को अपने आभार को व्यक्तिगत, अर्थपूर्ण और यादगार तरीके से व्यक्त करने का अवसर देता है।

योग दिलों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाता है : सीमा सिंह

मुंबई। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह भावनाओं को संतुलित करके लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। योग अभ्यास से तनाव दूर होता है, सहानुभूति जागृत होती है और एक-दूसरे के साथ जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांद्रा के ताजलैंड सन होटल में मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रेय द्वारा आयोजित योग दिवस पर बोलते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर अनेक जानी मानी हस्तियां और फिल्म स्टार उपस्थित रहे। श्रीमती सीमा सिंह के सुपुत्र श्रेय सिंह और सुपुत्री डॉ मेघना सिंह ने भी उपस्थित लोगों के साथ विभिन्न मुद्राओं में योग किया। भारी संख्या में बुजुर्ग युवा और बच्चे योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, नूपुर सनोन, मिकी मेहता, स्टेनबिन बेन, वीर पढ़ाडिया आदि का समावेश रहा। कुल मिलाकर मेघाश्रेय संस्था द्वारा आयोजित यह एक अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा।

बिजली व्यवस्था को लेकर विधायक राजन नाईक ने चीफ इंजीनियर से की बैठक

नालासोपारा वेस्ट स्थित पब्लिक रिलेशन ऑफिस में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में MSEDCL के चीफ इंजीनियर महेश भागवत के साथ नालासोपारा के विधायक राजन नाईक और मनोज बारोट मौजूद रहे। बैठक के दौरान वसई तालुका में बिजली आपूर्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दों और लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ईएचडब्ल्यू स्टेशन के कार्यों की प्रगति का आकलन किया तथा पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सामने आ रही बिजली कटौती, लो और हाई वोल्टेज की समस्या तथा अन्य तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए बिजली वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। विधायक राजन नाईक ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के साथ लगातार समन्वय और फॉलोअप किया जा रहा है, ताकि आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा कर लोगों को बेहतर बिजली सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

शाओमी ने लॉन्च किया रेडमी टर्बो 5

पटना। शाओमी इंडिया ने रेडमी टर्बो 5 लॉन्च करने की घोषणा की, जिससे भारत में रेडमी टर्बो सीरीज की शुरूआत हुई है। यह उन यूजर्स के लिए बनाया गया जो अपने स्मार्टफोन से ज्यादा की उम्मीद करते हैं, रेडमी टर्बो 5 एक प्रीमियम पैकेज में जबरदस्त परफॉर्मेंस, बेहतरीन बैटरी लाइफ, एडवांस्ड इमेजिंग क्षमताएं, शानदार एंटरटेनमेंट और भरोसेमंद मजबूती देता है। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बैटरी की चिंता हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। रेडमी टर्बो 5 इस समस्या को हल करने के लिए 7540 एमएएच की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसमें एडवांस्ड 16 प्रतिशत सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह भारत में लॉन्च किए गए किसी भी रेडमी स्मार्टफोन में दी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। मोटरस्पोर्ट्स की रफ़्तार और सटीकता से प्रेरित, रेडमी टर्बो 5 का डिजाइन बोल्ड है।

44.92 करोड़ रुपये के बढ़े हुए खर्च को मंजूरी देने का विवादित प्रस्ताव आखिरकार टला झ्र मनोज पाटिल

विरार। वसई-विरार शहर महानगरपालिका में प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान सड़कों के गड्ढे भरने के लिए किए गए 44.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी देने का विवादित प्रस्ताव आखिरकार स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की बैठक में टाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बैठक में इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद समिति ने फिलहाल इसे मंजूरी न देने का निर्णय लिया। विपक्ष के नेता मनोज पाटिल ने पहले से ही इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। उनका आरोप है कि आमसभा में प्रस्ताव पारित कराने में विफल रहने के बाद इसे विषय क्रमांक 22 के तहत स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी के लिए लाया गया था। मनोज पाटिल ने बताया कि वार्ड अ से क तक सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान 502.96 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक खर्च 547.88 करोड़ रुपये दशार्या गया है। इस प्रकार 44.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित वित्तीय वर्ष में जहां वास्तविक बजट प्रावधान 56.56 करोड़ रुपये था, वहीं प्रशासन द्वारा 161.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो निर्धारित राशि से 104.68 करोड़ रुपये अधिक है। पाटिल ने सवाल उठाया कि महानगरपालिका के नियमों के अनुसार किसी भी कार्य के लिए पहले मंजूरी आवश्यक होती है, फिर बिना पूर्व स्वीकृति के करोड़ों रुपये खर्च कर बाद में मंजूरी लेने की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रशासनिक कार्यकाल में हुए इस अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी किसकी है और किन परिस्थितियों में अधिकारियों ने इतनी बड़ी राशि खर्च की। पाटिल ने संदेह व्यक्त किया कि 44.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वास्तव में किन सड़कों पर किया गया, क्योंकि भारी खर्च के बावजूद वसई-विरार की सड़कों की स्थिति आज भी खराब बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महानगरपालिका के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अनेक जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में पूर्व में किए गए कथित अनियमित खर्चों के भुगतान पर जोर देना उचित नहीं है। मनोज पाटिल ने मांग की कि गड्ढों की मरम्मत के नाम पर किए गए 44.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और कार्यों की गुणवत्ता का किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष संस्था (थर्ड पार्टी एजेंसी) से तकनीकी ऑडिट कराया जाए। जब तक कार्यों की पारदर्शिता और वास्तविकता सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक स्थायी समिति को इस प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसे जनता के बीच ले जाया जाएगा। अंततः भाजपा सदस्यों के तीव्र विरोध और मामले से जुड़े विभिन्न सवालों को देखते हुए स्थायी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दिए बिना स्थगित कर दिया।